मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 06 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 5 – 11 फरवरी 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

प्रदेश भर में धरने, प्रदर्शनों के साथ भाकपा का अभियान संपन्न.....7

अडानी का गुब्बारा फूटा, निकला देश की लूट का सच.....11

भाजपा राज से देश को मुक्त करने के लिए एकताबद्ध होकर संघर्ष करें

हमारे विशेष संवाददाता द्वारा

30 जनवरी 2023 को राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के श्रीनगर में समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने सभी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक पार्टियों से अपील की कि वे एकजुट होकर काम करें और भाजपा राज से देश को मुक्त करने के लिए एकताबद्ध होकर संघर्ष करें।

श्रीनगर में जबर्दस्त बर्फबारी और ठंड के मौसम में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा विभिन्न पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कई नेताओं ने इस समापन कार्यक्रम के दौरान संबोधित किया।

इस कार्यक्रम में भाकपा महासचिव डी. राजा सबसे पहले वक्ता थे। एक चुनौती भरे समय में जनता के बीच एकता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए एक इतनी लंबी एवं कठिन यात्रा के लिए उनके दृढ़ संकल्प एवं समर्पण के लिए उन्होंने राहुल गांधी का अभिनंदन किया और बधाई दी।

अपना संबोधन प्रारंभ करते हुए डी. राजा ने उनके शहीदी दिवस पर महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गांधी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश धार्मिक भाईचारे और हिन्दू–मुस्लिम एकता के लिए था।

अपनी बात जारी रखते हुए डी. राजा ने कहा कि यह यात्रा समाप्त हो गई है, अतः अब आगे क्या किया जाना है और आगे क्या रास्ता है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए।

डी. राजा ने याद दिलाया कि किस तरह हम सबने देश की स्वतंत्रता के लिए मिलजुल कर संघर्ष किया, बलिदान किए और देश को ब्रिटिश राज से आजाद कराया। आज के हालात का तकाजा है कि तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट हो जाना चाहिए और दक्षिणपंथी फासिस्ट ताकतों से देश को मुक्त करने के लिए मिलजुल कर संघर्ष करना चाहिए। देश, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें भाजपा को हराने के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए।

भाकपा महासचिव डी. राजा द्वारा की गई अपील पर श्रोताओं और मंच पर बैठे नेताओं की प्रतिक्रिया अत्यंत उत्साहपूर्ण थी।

भाकपा महासचिव डी. राजा 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी मुख्यालय अजय भवन में ध्वजारोहण करते हुए, गणतंत्र दिवस पूरे देश में भाकपा के द्वारा संविधान रक्षा दिवस के रूप में मनाया गया

केन्द्रीय बजट 2023–24

जन विरोधी, विकास विरोध और अवास्तविक बजट

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल ने 1 फरवरी 2023 को निम्नलिखित बयान जारी किया:

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल केन्द्रीय बजट 2023–24 की सख्ती से निन्दा करता है कि यह बढ़ती हुई बेरोजगारी, बड़ती असमानता, मुद्रास्फीति और उभरते हुए बहुआयामी ग्रामीण संकट का संज्ञान लेने में विफल रहा है। बजट अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत को नकारता है और जैसे सब कुछ ठीक है की अवधारणा को मजबूत करता है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लिए आवंटन अनुपयुक्त है और यह मेहनतकश जनता के लिए बडा धक्का है कि जो उन्हें अधिक जोखिम के लिए असहनीय बनाने की तरफ धकेलकर उन्हें भूख तबाही में धकेल देगा।

कृषि पर आवंटन को 8500 करोड कम कर दिया है जबकि किसान उंची लागत की समस्या से पीड़ित हैं। उनकी सहायता के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। एमएसमएमई के लिए पूंजी सब्सिडी पर स्पष्टता नहीं है जो झूठे दावों की तरफ ले जाता है।

खाद्य सरुक्षा सब्सिडी को 2.8 लाख करोड़ से कम करके 1.97 लाख करोड कर दिया गया है। आईसीडीएस आवंटन को पिछले साल के बराबर ही रखा गया है और यदि मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा जाए तो यह पिछले साल से कम हो जाता है। नरेगा के लिए 2022–23 में आवंटन 89000 करोड़ था जिसे बजट में घटाकर 60000 करोड़ कर दिया गया है। इस प्रकार सभी सोशल सेक्टर का आवंटन कम कर दिया गया है।

बजट एक जन विरोधी, विकास विरोधी और वर्तमान जरूरतों को पूरा नहीं करने वाला अवास्तविक बजट है।

बापू की अंतिम विजय

तीस जनवरी, 1948 की शाम थी जब गांधीजी अपनी प्रार्थना सभा में, आभा और मनु के साथ जा रहे थे। नाथूराम गोडसे वहीं भीड़ में उनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही बापू नज़दीक आए, उसकी गोलियों से उनकी छाती छलनी हो गई। ''हे राम'' कहते हुए उन्होंने एक निगाह अपने कातिल पर डाली। उनमें न नफरत थी, न ही क्रोध। दर्द से काँपते उन होठों में करुणा का एक आभास–सा था जब वे लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरने लगे। जीवन चुक रहा था। उनका सिर गोद में लिये वे बालिकाएं रो रही थीं।

यह हत्या एक अदम्य भय का परिचय देती थी, जनमानस से पूरी तरह नकारे जाने का भय। यह असुरक्षा हर क्षण उनका पीछा करती थी, चुनौती देती थी। यह असुरक्षा शायद आज भी जीवित है हमारे देश की बहुलवादी दक्षिणपंथी धारा में। यह दिन हमें फिर से गांधी के बारे में जानने का मौका देता है, सांप्रदायिकता को फिर से जानने का भी। हमारी सभ्यता, संस्कृति में धर्म निरपेक्षता और विभिन्न धारओं के गंगा–जमुनी रंग कितनी गहराई से घुले हैं, और हमारे संविधान की बुनियाद में वे सशक्त सिद्धांत के रूप में किस तरह अंधेरे में हमें रोशनी देते हैं आगे बढ़ते रहने के लिये, यह सब एक बार फिर से उभर आया है आज के विमर्श में।

महात्मा गांधी की हत्या स्वयं इस बात को उजागर करती है कि धर्मनिरपेक्षता और एकता के रूप में बापू कितनी बड़ी चुनौती बन गए थे उन सबके लिये, कि शारीरिक रूप से भी उन्हें मिटाने की कोशिश की गई। वे चले गए, पर उनके विचार जीवित हैं, चुनौती उतनी ही बड़ी है उनके लिये जितनी शायद उनकी सांप्रदायिक विचारधारा और उसे स्थापित करने की सारी कोशिशें भी नहीं है। सांप्रदायिक आघातों का सामना करने के लिये वैचारिक स्तर पर जो कोशिशें चलती है, कई बार राजसत्ता के विरूद्ध भी उन्हें जाना पड़ता है। यह सत्ता, जब दक्षिणपंथियों के हाथ में होती है तो वह किताबों को प्रतिबंधित करती है, मीडिया को खामोश करती है और उभरती हुई विरोधी ताक़तों को सालों कैद में, बिना किसी मुकदमे के बंद कर देती है। पर इस सबसे सफलता हमेशा मिलती नहीं।

औपनिवेशिक शासन के युग में, सांप्रदायिक विचारधारा का उपयोग एक अस्त्र के रूप में भी होता था, और इसकी बुनियाद होती थी ''तोड़ो और राज करो'' की नीति। राजसत्ता द्वारा पूरी तरह इसे समर्थन मिलता था। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन अहिंसा के आधा पर शुरू किया गया तो इसे बर्बरता से कुचलने की कोशिश की गई। इस आंदोलन में हर भारतीय, चाहे वह किसी भी संप्रदाय का हो, जब भाग लेता था तो पूरी तरह एकजुट होकर, बिना किसी भेदभाव के।

इसका एक ज्वलंत उदाहरण था दांडी मार्च, जो नमक क़ानून के विरूद्ध 1930 में हुआ था। गांधीजी द्वारा छेड़े गए उस आंदोलन में उनका शांत सविनय अवज्ञा (विरोध), अहिंसा और अभय, जो किसी भी अत्याचार से ऊपर थे, सशक्त रूप से सामने आये। ये सारे उनके वे हथियार थे जिससे वे विश्व शांति के लिये हर चुनौती का सामना करने के लिये तैय्यार रहते थे और इस चुनौती में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भी था। पच्चीस हजार स्वयंसेवक, एक दूसरे के संप्रदाय, जाति से बेपरवाह, धारासना सॉल्ट वर्क्स के पास पहुंच रहे थे, जो दांडी से दूर नहीं था। यह गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एक हिस्सा था।

ये सभी मौन थे और धीरे–धीरे बढ़ रहे थे। एक हिस्सा पानी

संपादकीय

और कीचड़ से भरे गड्ढों को पारकर रहा था और कांटोवाले तार से घिरे अपने लक्ष्य स्थल की ओर बढ़ रहा था। अचानक एक निर्देश गूंजा और पुलिस के सिपाही उन पर झपट पड़े। आंदोलनकारियों में से किसी ने अपने को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। लाठियां बरसती रहीं, सिर, हाथ, पैर घायल होते रहे, जब तक चलने की ताक़त थी, वे बढ़ते रहे और फिर जमीन पर गिरते रहे। जुलूस आगे बढ़ता रहा। बिना किसी प्रतिरोध या लड़ाई के, वे मौन, अनुशासित कदमों से आगे बढ़ रहे थे

सत्याग्रहियों को इस सारे आत्मत्याग से क्या मिला?

वे आगे नहीं पहुंच पाए, नमक क़ानून भी वापस नहीं लिया गया पूरी तरह। लेकिन विश्व यह समझ रहा था कि बात सिर्फ उतनी ही नहीं है। नमक सत्याग्रह से ये तथ्य स्पष्ट हो चुका था कि गांधीजी का यह नया अस्त्र, जो हर घात–प्रतिघात से निरपेक्ष, शांत और हर आक्रमण, चाहे वह कितना भी क्रूर हो, की अवज्ञा करता हुआ आगे बढ़ता है दृढ़ता से। इस शक्ति के साथ अब भारत विश्व की निगाहों से सीधे नज़र मिला सकता था, न कम, और न ज्यादा। यूरोप भी इसे अब समझ रहा था।

नमक सत्याग्रह का अंतिम चरण अप्रैल 1930 को संपन्न हो गया।

गांधीजी ने बाद में भी कहा था कि हमारी गरीब जनता पर नमक क़ानून एक अत्याचार है। वे नमक अपने घरों में बनाएं, क़ानून तोड़कर, और परिणाम भी भुगतने को तैय्यार रहें।

गांधीजी विश्व, जिसमें भारत भी शामिल था, उसे एक परिदृश्य मानते थे, जिसमें मानव चेतना ही केंद्र में थी, जो निर्भयता और अहिंसा के साथ ही विकसित होती है। बंगाल में नोआखाली में फैली सांप्रदायिक हिंसा, जहां वह हफ्तेभर के लिये जाकर महीने से भी अधिक समय रूक गए थे, इसी का एक उदाहरण है कि तड़पती जनता का वह दर्द उनका अपना व्यक्तिगत हो जाता था। उन्होंने कहा था, ''मैं यहां अपने सिद्धांतों को ही साबित करने आया था, अहिंसा और अभय का सिद्धांत। आज अगर नोआखाली बर्बाद होता है तो भारत भी बर्बाद हो जाएगा।'' वे परिवर्तन में विश्वास करते थे और इसके हर दौर के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश करते थे।

लुई फिशर, उनकी जीवनी के लेखक, जिन्होंने ''लाइफ ऑफ महात्मा गांधी'' नामक पुस्तक लिखी थी, ने एक बार उनसे कहा था कि वे अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में विस्तार से बताएं।

गांधी जी का उत्तर था, ''गांवों में किसान टैक्स देना बंद कर देंगे। बिना सरकारी अनुमति के ही वे नमक बनाना शुरू कर देंगे। यह सब बहुत ही छोटा–सा क़दम लगता है। नमक टैक्स से ब्रिटिश सरकार को मामूली–सी ही रक़म मिलती है। लेकिन इसी टैक्स को देने से मना करने में किसान का आत्मविश्वास बढ़ता है कि वह स्वयं भी निर्णय लेकर क़दम उठा सकता है। इसका दूसरा क़दम होगा ज़मीन पर कब्जा करना। वस्तुतः जमीन पर उन्हीं का अधिकार होता है जो उस पर काम करते है। इस स्थिति में उन पर हिंसा हो भी सकती है और नहीं भी। मुश्किल से पंद्रह दिनों का झमेला हो सकता है लेकिन हम सोचते हैं परिस्थिति पर नियंत्रण के लिये उतना समय क़ाफी है। यह किसानों द्वारा जमीन को जब्त किया जाएगा, बिना जमींदार को कोई मुआवजा दिए।''

उन्होंने यह भी कहा, ''मैंने मज़दूरों के सामने यह सत्य भी स्पष्ट किया है कि पूंजी कोई सोना या चांदी नहीं होती, यह तो उन मज़दूरों के हाथों, पैरों, और कुशलता तथा बुद्धिमत्ता में होती है। एक बार जब मज़दूर इसे आत्मसात् कर लेगा तो उसे मेरी जरूरत नहीं होगी, वह स्वयं ही अपनी इस शक्ति का उपयोग कर लेगा।''

यही महात्मा गांधी थे, जो पूरे संदर्भ और उसके सार को लेकर चलते थे।

भाकपा ने निन्दा की यूपी के मुख्यमंत्री के बयान की

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल ने 30 जनवरी को निम्नलिखित बयान जारी किया:

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान कि निन्दा की जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना राष्ट्रवाद से की है।

किसी धर्म विशेष को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा देना असंवैधानिक और निंदनीय है। सभी पृष्ठभूमि के स्वतंत्रता सेनानियों ने एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला किया। उनके बलिदानों ने हमें एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनाया। आरएसएस तब भी लोगों को बांट रहा था और अब भी बांट रहा है। यह भारतीय संविधान की भावना के खिलाफ है और संविधान के धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने को कमजोर करने के लिए आरएसए–भाजपा गठबंधन के सच्चे चरित्र को व्यक्त करता है।

हमें विश्वास है कि पिछले 74 वर्षों से धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान को बरकरार रखने वाले भारतीय लोग इसके मूल मूल्यों पर इस निर्लज्ज हमले को स्वीकार नहीं करेंगे। हम सभी प्रगतिशील वर्गों से अपील करते हैं कि वे संविधान के मूल मूल्यों की दृढ़ता से रक्षा करें और उन सभी का विरोध करें जो संविधान को कमजोर कर रहे हैं।

भाकपा की मांग: अडानी डील्स की गहन जाचं हो

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल ने 28 जनवरी, 2023 को निम्नलिखित बयान जारी कर अडानी सौदों की गहन जांच की मांग की:

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सचिवालय बार–बार इस ओर इशारा करता रहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली आरएसएस–बीजेपी की संयुक्त सरकार द्वारा अपनाई गई कारपोरेट और बड़ी–व्यावसायिक घरानों की समर्थक नीतियों के परिणामस्वरूप अडानी एवं अन्यों के द्वारा प्राकृतिक संपत्ति की लूट हो रही है। एलआईसी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मोदी सरकार ने अडानी कंपनियों के शेयरों में निवेश करने के लिए कहा है। अडानी समूह का अब बंदरगाहों, हवाई अड्डों और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर नियंत्रण हो गया है। मोदी के सत्ता में आने के बाद अडानी समूह का अचानक विकास सरकार से मिले संरक्षण का प्रमाण है। अडानी समूह द्वारा कथित हेरफेर के कारण औसत भारतीय निवेशक और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों सहित निवेशक पहले से ही भारी नुकसान में हैं। भाकपा अडानी समूह के सभी सौदों की सक्षम अधिकारियों द्वारा गहन जांच की मांग करती है ताकि आगे होने वाले नुकसान को रोका जा सके। पार्टी, राष्ट्रीय और प्राकृतिक संपदा की लूट के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को, जो नजीर बन सके, ऐसी सजा देने की भी मांग करती है।

ओलों, बारिश और पाले आदि से हुई फसल हानि की भरपाई की जाये

भाकपा ने किसान हित में की मांग

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. गिरीश ने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तरी–पश्चिमी राज्यों के कई हिस्सों में कई दिनों तक हुयी बारिश खासकर ओलावृष्टि से फसलों को काफी क्षति पहुंची है, और इन राज्यों की सरकारों ने अभी तक किसानों की कोई सुध–बुध नहीं ली है। इससे पहले तापमान गिरने और पाला पड़ने से भी फसलों को व्यापक हानि हुई।

एक प्रेस बयान में भाकपा नेता ने कहा कि तिलहनों–सरसों, अरहर, राई आदि तथा आलू की फसल पर इसका व्यापक असर पड़ा है। आलू की परनालियों में पानी भर जाने से उसके गल जाने की आशंका है तथा पाला और पालाजनित रोगों से आलू को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। खबर है कि बर्फबारी से पर्वतीय क्षेत्रों में सेब की फसलों को भी भारी हानि पहुंची है।

डॉ. गिरीश ने आरोप लगाया कि राज्य सरकारें किसानों के सरोकारों की अनदेखी कर रही हैं। हानि की भरपाई तो दूर अभी तक उसका सर्वेक्षण कराने तक की खबर तक नहीं है। केन्द्र प्रायोजित फसल बीमा योजना अडानी की कंपनियों के माफिक लुटेरेपन में जुटी हैं।

उन्होंने कहा कि जहां भी हानि हुयी है भाकपा किसानों के पक्ष में यथासंभव आवाज उठा रही है। राजस्थान में तो भाकपा ने 8 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे जाने का निर्णय लिया है वहीं उत्तर प्रदेश में 4 एवं 5 फरवरी को होने जा रही राज्य कार्यकारिणी की बैठक में इस पर विचार किया जाना है।

भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान

जींदः 26 जनवरी 2023 को जींद (हरियाणा) की नई अनाज मंडी में एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी के कानून समेत किसानों के अन्य सवालों पर देश में एक सघन किसान आंदोलन की आहट इस महापंचायत में सुनाई दी। संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में फैसला किया गया कि 9 फरवरी को कुरूक्षेत्र में एसकेएम की मीटिंग होगी जिसमें किसानों की मांगों पर संसद मार्च की तारीख तय की जायेगी। इस महापंचायत में हरियाण के 14 किसान संगठन एवं दो धरना कमेटियों ने भाग लिया। हरियाणा के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं दिल्ली के 50 हजार से ज्यादा किसानों, मजदूरों ने भाग लिया।

महापंचायत में अखिल भारतीय किसान सभा (अजय भवन) ने पूरे जोशो खरोश के साथ भागेदारी की और हरियाणा राज्य से लगभग 10 जिलों से किसानों, मजदूरों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। हरियाणा के अलावा पंजाब एवं उत्तर प्रदेश से भी किसान सभाई इस रैली में शामिल हुए। मीडिया के मुताबिक यह एक ऐतिहासिक महापंचायत है, जिसने हाजिरी के लिहाज से पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं, जींद की अनाज मंडी और पूरे शहर में झंडे लिए हुए किसान संगठनों के साथी ही नजर आ रहे थे। संयुक्त किसान मोर्चा के अलग–अलग घटकों ने लंगर चाय एवं मेडिकल सुविधा के लिए प्रबंध कर रखे थे। कई गांव के किसानों ने देसी घी के

सुखदेव सिंह जम्मू

हलवे एवं खीर के लंगर लगाए हुए थे, जिससे महापंचायत की शोभा बन रही थी और लोग बड़े इत्मीनान से रैली को सुन रहे थे और भिन्न–भिन्न व्यंजनों का लुत्फ भी ले रहे थे।

अखिल भारतीय किसान सभा (अजय भवन) के राष्ट्रीय महासचिव अतुल कुमार अनजान जी ने मंच से सभा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया, इसके अलावा हरियाणा से साथी धर्मपाल सिंह चौहान एवं पंजाब के राज्य अध्यक्ष बलदेव सिंह निहालगढ़ ने भी संबोधित किया। हरियाणा राज्य संयोजक डॉक्टर सुखदेव सिंह जम्मू ने मंच संचालन करने में संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य संगठनों से मिलकर सहयोग किया। यह महापंचायत आने वाले समय में किसान की सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं संपूर्ण कर्जा माफी की मांग को लेकर चलने वाले संघर्ष का बिगुल साबित होगी। भाजपा सरकार को हरियाणा एवं केंद्र से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेते हुए सभा समाप्ति की घोषणा की गई।

सभा को हनान मोल्ला, राकेश टिकैत, डॉक्टर दर्शन पाल, जोगिंदर सिंह उग्राहा, राजा राम एवं सत्यवान सरीखे राष्ट्रीय किसान नेताओं ने संबोधित किया। अतुल कुमार अनजान ने सभा को संबोधित करते हुए देश की जनता से भाजपा नीत सरकार को हरियाणा राज्य एवं केन्द्र से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया ताकि भारत के संविधान एवं लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जा सके।

महापंचायत के मंच से किसान नेताओं ने केन्द्र सरकार पर लगातार बढती महंगाई, बेरोजगारी और बढते भ्रष्टाचार को लेकर तीखा हमला बोला। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार देश को कारपोरेट घरानों के हवाले कर रही है, महंगाई व बेरोजगारी पर सरकार का कोई नियंत्रण नही है इसके चलते सबसे बुरी हालत किसान और मजदूर की है।

महापंचायत में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह पर जूनियर महिला कोच द्वारा लगाए आरोपों के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा अभी तक मंत्री को बर्खास्त नही करने पर सरकार की निंदा करते हुए संदीप सिंह को बर्खास्त एवं गिरफ्तार करने की मांग की गई। महापंचायत में हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने के मूल्य में की गई 10 रुपये क्विंटल की वृद्धि को किसानों के साथ भद्दा बताते हुए गन्ने का उचित भाव देने की मांग की गई।

निराशाजनक और खोखला है बजट 2023–24: एटक

एटक सचिवमंडल ने केन्द्रीय बजट 2023–24 के सम्बंध में 1 फरवरी 2023 को निम्न बयान जारी कियाः

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने धूम–धड़ाके के साथ उसे 'अमृतकाल बजट' का नाम देते हुए अपना अंतिम बजट पेश किया। जैसा कि इस सरकार के कार्यकाल में सामान्यतः होता है जबर्दस्त लफ्फाजी और प्रधानमंत्री के गुणगान के साथ यह बुरी तरह खोखला बजट है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बजट में कुछ भी नहीं। मतदाताओं को रिझाने के लिए छिटपुट बातों के अलावा उसमें कुछ भी ऐसा नहीं जिसका लक्ष्य जनकेन्द्रित आर्थिक वृद्धि और मानवीय विकास हो। उनके भाषण में लफ्फाजी और झूठ के अलावा कुछ न था। बजट में जिन अनूमानों (एस्टीमेट्स) को उपलब्धियों के रूप में पेश किया गया वह सच से कोसों दूर थे।

बजट में समावेशी विकास, अन्तिम व्यक्ति तक पहुंचना, युवा शक्ति जैसी जिन सात प्राथमिकताओं को गिनाया गया है, वह सब खोखली बातें हैं जिनमें कोई सारतत्व नहीं।

जनता से सरोकार रखने वाले किसी भी वास्तविक मुद्दे का समाधान नहीं किया गया है। ट्रेड यूनियनें पुरानी पेंशन स्कीम, सभी को सामाजिक सुरक्षा, स्कीम वर्करों को नियमित करने, खेत मजदूरों समेत सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी आदि की मांगें करती रही हैं। बजट में किसी मांग के सम्बंध में कुछ नहीं किया गया। बजट में राष्ट्र और उसकी उस 94 प्रतिशत श्रम शक्ति के हितों को पीछे छोड़ दिया गया है जो सकल घरेलु उत्पाद के 60 प्रतिशत का योगदान करती है।

बजट में दीर्घकालिक रोजगार और गुणवत्तापूर्ण रोजगार सृजन के लिए कुछ भी नहीं। हर वर्ष काम की तलाश में 80 लाख नये लोग रोजगार बाजार में दाखिल होते है। बेरोजगारी 34 प्रतिशत के चरम शिखर पर है। बजट में मांग आधारित स्किलिंग (हुनर) की चर्चा की गयी है। हुनर औपचारिक शिक्षा से आता है। भारत में औपचारिक शिक्षा की वास्तविकता को अनदेखा कर स्किलिंग की बात करना कोई मायने नहीं रखता। यह एक त्रुटिपूर्ण समझ है जिसमें प्रतिबद्धता का अभाव है। देश में अधिकतम युवा आबादी है, बजट में 'युवा शक्ति' को तथाकथित प्राथमिकता उसका लाभ उठाने में विफल है। उद्योग के लिए नवयुग का रास्ता तकनीकी तौर पर शिक्षित युवाओं के एक अत्यंत छोटे हिस्से के लिए लक्षित है और पात्र युवाओं का बड़ा हिस्सा इससे बाहर रह जाता है।

शिक्षा पर खर्च अपर्याप्त है। भारत में औसत स्कूल शिक्षा की दर बेहद कम हो गयी है। बजट में उच्च शिक्षा पर खर्च की बात कही गयी है। विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में दाखिल करने का ब्लू प्रिन्ट पहले ही बनाया जा चुका है। लगता है उच्च शिक्षा को यह प्रोत्साहन उसी योजना से मेल खाता है। भाजपा अभी तक शिक्षा पर सकल घरेलु उत्पाद के 3 प्रतिशत से भी कम का आवंटन करती रही है।

सिकल सैल रक्ताल्पता को 2047 तक खत्म करने के विशेष कार्यक्रम के अलावा बजट में कोई स्वास्थ्य खर्च नहीं है। स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में कमी से भारत में गरीबी बढ़ी है।

कृषि में खर्च को किसानों को खैरात बख्शने की हद तक घटा दिया गया है जो एक चुनावी हथकंडा है। मछली पालन के सम्बन्ध में भविष्य के लिए कुछ योजनाएं हैं जिनके लिए बजटीय आवंटन कम है। मनरेगा एक मांग आधारित रोजगार योजना है। इस योजना के आवंटन में कटौती से रोजगार चाहने वाले लगभग 7 करोड़ लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ेगा।

सात लाख तक की आमदनी को टैक्स से छूट देकर मध्यम वर्ग को रिझाया गया है। यह औपचारिक वैतनिक श्रमशक्ति का एक छोटा हिस्सा है, यह वोट बैंक को आकर्षित करने का तरीका है।

शेष पेज 6 पर...

गणतंत्र दिवस पर किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैलियां

मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आपको काले कृषि अधिनियमों को खत्म नहीं करके भारतीय किसान समुदाय को धोखा दिया है। यहां तक कि यह मुद्दा वर्तमान संसद सत्र के एजेंडे में भी नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि अगर मोदी सरकार उन काले कृषि अधिनियमों को वापस नहीं लेती है, तो एक और जुझारू किसान आंदोलन अपरिहार्य होगा। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा किए गए आह्वान के जवाब में, खम्मम शहर में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली आयोजित की गई। रैली पवेलियन मैदान से शुरू हुई और मयूरी सेंटर, इलेंदु एक्स रोड, ममता सर्कल, रोटरी नगर, श्री श्री सर्कल से होते हुए अंत में नए समाहरणालय कार्यालय पहुंची।

इस अवसर पर पवेलियन मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए बी हेमंत राव तेलंगाना राज्य अध्यक्ष तेलंगाना रायथू संघम और पी सुदर्शन राव राज्य अध्यक्ष तेलंगाना रायथू संघम ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार कृषि के निजीकरण के अलावा तीन नए काले कानून लाई है। किसानों को नुकसान पहुँचाने के लिए कृषि कानू लाये गये हैं। भारतीय किसान समुदाय ने एक लंबी अवधि तक एक एकजुट ऐतिहासिक आंदोलन चलाया है। भाजपा ने सोचा है कि उनका पतन निश्चित है इसलिए उन्होंने नए नाटक के लिए पर्दा उठा दिया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने घोषणा की है कि वे काले कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं।

लेकिन व्यावहारिक रूप से इसे कानून के रूप में लाने के लिए यह नाटक कर रहा है। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र को कारपोरेट मित्रों के हवाले करने का हर संभव प्रयास कर रही है। कारपोरेट्स को पहले ही लाखों करोड़ रुपये की रियायतें दी जा चुकी हैं। इसके अलावा यह संबंधित कानूनों में संशोधन करके कारपोरेट्स द्वारा लिए गए लाखों करोड़ के कर्ज को भी माफ कर रहा है। वही सरकार किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं कर रही है? प्राकृतिक आपदाओं और सरकार की विफलताओं के कारण किसान कर्ज की खाई में गहराई तक डूबे हुए हैं। आग में घी डालने के लिए केंद्र सरकार बिजली अधिनियम 2020 लायी है। पूरे भारत के किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कई दशकों से कर रहे हैं। इन सिफारिशों को कानून बनाकर बिना किसी और देरी के तुरंत लागू किया जाए।

डी. रमेश, एम रमेश, प्रकाश, एम नागेश्वर राव अध्यक्षमंडल में थे। पी प्रसाद, भाकपा जिला सचिव, के गोविंद राव, आदि जन संगठनों के नेता एस के जानिमियां, बी रामकोटी, एम वेंकट रेड्डी, संबाशिव रेड्डी, बी रामबाबू, सचिव, तेलंगाना रायथु संघम, गोकिनेपल्ली वेंकटेश्वर राव, रायथु कुली संघम राज्य नेता, राजेंद्र प्रसाद, एसके मीरा, टी रामा राव, ए रामकोटैया, स्वर्ण रमेश, तम्मीसेट्टी वेंकटेश्वरलू, कूचिपुडी रवि, भाकपा नेता, पोटू कलावती, थाटी वेंकटेश्वरलू, रवि शिवरामकृष्ण, इतिकला रामकृष्ण,जी लक्ष्मीनारायण, वेमुलाकोंडा रमेश, सोमैया, आनंद राव और भरत आदि ने रैली में भाग लिया।

पूरे तेलंगाना में ट्रैक्टर रैलियां हुई। उपरोक्त मांगों के अलावा मांगें की गयी और हैदराबाद में आरटीसी चौराहे से इंदिरा पार्क तक रैली निकाली गई, न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिनियम, कर्ज माफी अधिनियम लाया जाए, किरायेदार किसानों, किसानों और खेतिहर मजदूरों को 5,000/– रू. की पेंशन, भूमि पर अधिकार पत्र वन अधिकार अधिनियम के अनुसार ऋण पात्र कार्ड और बैंक ऋण दिए जाएं और किसानों पर दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाए।

संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पस्य पद्मा, सागर, आर चन्द्रशेखर, कोटेश्वर राव, जे वेंकन्ना, टी वेंकटराम, और रामवत अंजैयानायाक आदि ने रैली में भाग लिया।

बेगूसराय (बिहार)

ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 26 जनवरी 2023 को किसानों के राष्ट्रव्यापी ट्रैक्टर मार्च के आह्वान पर बेगूसराय समाहरणालय पर ट्रैक्टर के साथ किसानों के रोषपूर्ण प्रदर्शन पॉलिटेक्निक कॉलेज बेगूसराय के निकट से गगनभेदी नारा लगाते हुए प्रारंभ हुआ। सैंकड़ों ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के साथ मार्च का नेतृत्व बिहार राज्य किसान सभा के महासचिव अशोक प्रसाद सिंह, बिहार राज्य किसान सभा जमाल रोड के अध्यक्ष पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह, किसान सभा के जिला सचिव अरविंद सिंह, कार्यकारी जिला सचिव दिनेश सिंह, जिला सचिव दयानिधि चौधरी, सुरेश यादव, ऑल इंडिया किसान महासभा के नेता राजेश श्रीवास्तव, जय किसान आंदोलन के महासचिव डॉक्टर रंजीत कुमार, पैक्स अध्यक्ष राम नरेश महतो, नागेंद्र राय, डॉ. रामचरित्र महतो, नवीन कुमार एवं राम प्रमोद सिंह आदि कर रहे थे।

ट्रैक्टर मार्च हर–हर महादेव चौक, ट्रैफिक चौक, टाउन थाना, नगरपालिका चौक एवं नवाब चौक होते हुए कचहरी चौक पर सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता राजेंद्र सिंह ने की। इस अवसर पर किसान नेताओं ने भारत सरकार और बिहार सरकार की किसान विरोधी नीतियों की खुलकर आलोचना की। मोदी सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि जो वादा किया है, उसे निभाना होगा। नहीं तो गद्दी से जाना होगा। किसानों ने यह ठान लिया है। किसानों के साथ धोखा देने वालों का राज देश में नहीं चलेगा। बिहार में खाद की कालाबाजारी और धान अधिप्राप्ति में धांधली के खिलाफ किसान नेताओं ने आक्रोश व्यक्त किया। विगत 3 माह से बक्सर के चौसा में धरना दे रहे किसानों की मांगो को अविलंब पूरा करने की मांग किसान नेताओं ने की। आंदोलन की मुख्य मांगें निम्नलिखित है:

(1) सी–2 के आधार पर लागत का डेढ़ गुना दाम सभी कृषि उत्पादों के लिए एमएसपी कानून की गारंटी हेतु संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं से बात कर अविलंब किसान हित में कमेटी बनाई जाए।

(2) दिल्ली किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा देने, उनके परिवार को मुआवजा तथा उनका शहीद स्मारक हेतु स्थल आवंटित हो।

(3) लखीमपुर खीरी के किसानों की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए।

(4) किसान आंदोलन में किसानों पर किए गए सभी मुकदमों को अविलंब वापस लिया जाए।

(5) कृषि एवं किसान विरोधी बिजली बिल विधेयक 2022 को वापस लिया जाए।

(6) किसानों को सभी प्रकार का कृषि ऋण से कर्ज मुक्त किया जाए।

(7) सभी किसानों से धान खरीदने की गारंटी हो।

(8) प्रीमियम मुक्त सभी फसलों के लिए फसल बीमा योजना पुनः बिहार में चालू हो।

(9) 60 साल की उम्र से सभी पुरुष एवं महिला किसानों को 10000/–रू. मासिक पेंशन दिया जाए।

(10) बिहार के चौसा के किसानों द्वारा विगत 3 महीना से हो रहे धरना की मांग को अविलंब पूरा किया जाए।

मुक्ति संघर्ष पढ़िए

चन्दे की दरः

वार्षिक	: 350 रूपये
अर्द्धवार्षिक	: 175 रूपये
एक प्रति	: 7 रूपये
एजेंसी डिपोजिट	
प्रति कापी	: 70 रूपये

खाता नामः **मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक**
बैंकः **सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया ब्रांच**
चालू खाता संख्याः **1033004704**
आईएफसी कोडः **सीबीआईएन0280306**

कापी मगाने के लिये लिखें:
व्यवस्थापकः मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक
अजय भवन, 15–का. इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
नयी दिल्ली–110002

नोटः डीडी और चेक केवल ''मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक'' के नाम होना चाहिए।

कम्युनिस्ट नेताओं की जीवनी–79

सरला शर्मा: असाधारण कम्युनिस्ट एवं महिला नेता

अनिल राजिमवाले

सरला गुप्ता (शर्मा) का जन्म 17 अप्रैल 1921 को पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित हवेली हैदर कुली में हुआ थ। उनका खाता–पीता मध्यम–वर्गीय परिवार था। सरला 101 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहीं। उनके पिता का नाम श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता था और माता का श्रीमती शकुंतला। पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट थे।

पुरानी दिल्ली का यह इलाका बड़े ऐतिहासिक महत्व का है। मध्ययुगीन हवेलियां, बंगले, नवाबों के महल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अंग्रेजों के मकान, संकरी गलियां, ऐतिहासिक दुकानें, वे सब इतिहास बयान करते हुए हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं। इस प्रकार सरला को बड़ा ही अनुकूल वातावरण मिला। इन्हीं गलियों में आम मजदूर तथा श्रमिक एवं कुली आज भी कड़ी मेहनत करते हुए पाए जाएंगे। इस प्रकार यह जगह ज्ञान एवं संघर्ष का स्थान भी है।

इंद्रप्रस्थ स्कूल में शिक्षा

सरला की आरंभिक शिक्षा ऐतिहासिक जामा मस्जिद के नजदीक स्थित इंद्रप्रस्थ स्कूल में हुई थी। इस स्कूल की स्थापना की पहल सरला के दादा लाला जुगलकिशोर द्वारा की गई। यह दिल्ली में लड़कियों का प्रथम स्कूल था। स्कूल का उद्घाटन 19 मई 1904 को किया गया। वे सुप्रसिद्ध शिक्षाविद्, स्वतंत्रता सेनानी तथा कांग्रेस नेता एनी बेसंट द्वारा प्रेरित थे। स्कूल लाला बालकिशन दास के मकान में स्थित था। उस जमाने में लड़कियों की शिक्षा पर कड़ी सामाजिक पाबंदी थी और काम आसान नहीं था।

स्कूल धीरे–धीरे राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया। इसमें कई नेताओं की शिक्षा हुई। इनमें जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला भी थीं जो इसी स्कूल में पढ़ी थीं। स्कूल की प्रिंसिपल एक ऑस्ट्रेलियन महिला मिस एल. जीश मेनर थीं, जो एनी बेसंट की अनुयायी थीं। होम रूल लीग का कार्यालय इसी स्कूल में स्थित था और जल्द ही स्कूल कांग्रेस की गतिविधियों का केंद्र बन गया। फलस्वरूप अंग्रेजों ने स्कूल को फंड देना बंद कर दिया। लेकिन बाबू जुगलकिशोर ने फंड इकट्ठा कर स्कूल चलाया।

सरला गर्ल गाईड भी थी लेकिन उसने यूनियन जैक फहराने और 'लॉग लिव द किंग' गाने का विरोध किया। उसने विशेष तौर पर ''हम पर शासन करने के लिए आपको लंबी उम्र लगे'' लाइन का तीखा विरोध किया गया।

इस प्रकार सरला का पालन–पोषण राष्ट्रवादी वातावरण में हुआ। यहां दिल्ली नौजवान सभा भी सक्रिय थी। दिल्ली में कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक बहाल सिंह भी नौजवान सभा से जुड़े हुए थे।

दिल्ली में अप्रैल 1930 में नमक सत्याग्रह बड़े ही प्रभावशाली ढंग से हुआ था। यह 6 अप्रैल को यमुना नदी के दलदली एवं नमकीन पानी के किनारे आरंभ हुआ। दरियागंज तथा अन्य जंगलों में सत्याग्रह कैम्प खोले गए। इनमें महिलाओं ने बढ़चढ़कर भाग लिया। इंद्रप्रस्थ स्कूल तथा इंद्रप्रस्थ वीमेन्स कॉलेज की लड़कियां इसमें बड़ी सक्रिय रहीं।

अपनी स्कूली शिक्षा समाप्त करके सरला इंद्रप्रस्थ गर्ल्स कॉलेज में भर्ती हो गई जहां उसने 1935 से 1940 तक पढ़ाई की। 1942 में उसने हिन्दू कॉलेज में दाखिला ले लिया और अर्थशास्त्र में एम.ए. किया।

राजनीति के संपर्क में

राजनीति के साथ सरला का प्रथम संपर्क कांग्रेस के जरिये हुआ। जब वह छात्रा ही थी तो उसने 5,000 लोगों की रैली में भाग लिया। अन्य के साथ मिलकर उसने नारे लगाए: ''रखनी नहीं सरकार जालिम, रखनी नहीं''। उस वक्त सरला ने पं. सुंदरलाल की एक पुस्तक ''भारत में अंग्रेजी राज'' पढ़ी थी। उस पुस्तक पर अपनी पाबंदी लगी हुई थी। चटगांव सशस्त्र विद्रोह के बारे में पढ़ते वक्त उन्हें कम्युनिस्ट विचारों की जानकारी हुई। उनपर प्रीतिलता वद्दार तथा कल्पना जोशी का गहरा प्रभाव पड़ा। बंबई के टेक्सटाइल मजदूर आंदोलन से भी वे प्रभावित हुई। सरला गुप्ता ने राहुल, प्रेमचंद, इ. की पुस्तकें व्यापक तौर पर पढ़ीं। साथ ही विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन संबंधी साहित्य भी पढ़ा।

स्टूडेंट्स फेडरेशन में

सरला ने छात्राओं का वालंटियर ग्रुप गठित किया। वह 1938 में स्टूडेंट्स फेडरेशन में शामिल हो गई। और जल्द ही दिल्ली एस.एफ. की संयुक्त सचिव और फिर कोषाध्यक्ष बनाई गई। उसके हाथों में एक छोटा टाईपराइटर हुआ करता था जिसे लेकर वह ट्राम इत्यादि में घूमा करती। वह भागीरथ प्लेस, चांदनी चौक में एस. एफ. के दफ्तर नियमित जाया करती। बाद में कार्यालय कटरा शाहंशाही चला गया। वह बग्गी में भी घूमा करती।

एस.एफ से कम्युनिस्ट पार्टी में

दिल्ली स्टूडेंट्स फेडरेशन का तीसरा सम्मेलन 13–14 नवंबर 1938 को संपन्न हुआ। उसका उद्घाटन सरोजिनी नायडू ने किया और उसे सुभाषचंद्र बोस ने संबोधित किया। सरला गुप्ता इसकी संयुक्त सचिव चुनी गई।

बहाल सिंह डी.पी.सी.सी. के सचिव थे। साथ ही वे कम्युनिस्ट भी थे। वे विद्यार्थी नेताओं के साथ निरंतर संपर्क

में बने रहते। उन्होंने वाई.डी. शर्मा, सरला गुप्ता, फारूकी, संघी, शकील,इ. नेताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। वे सभी 1939 में प्रथम कम्युनिस्टों में शामिल हो गए। बहाल सिंह वाई.डी. शर्मा को कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन (1938) में ले गए।

उन दिनों दिल्ली के अधिकतर कम्युनिस्ट कांग्रेस में हुआ करते। भा.क.पा. की पोलित ब्यूरो के सदस्य आर. डी. भारद्वाज की देखरेख में 1939 में दिल्ली में पार्टी की संगठन समिति गठित की गई। बहाल सिंह इसके सचिव बनाए गए। उनकी गिरफ्तारी के बाद वाई.डी. शर्मा सचिव बने। 1943 में पार्टी पर से पाबंदी हटा दी गई। 3 जनवरी को जामा मस्जिद क्षेत्र में पार्टी का प्रादेशिक सम्मेलन 23 से 25 जनवरी 1944 को आयोजित किया गया।

सम्मेलन को पोस्टरों, चित्रों एवं झंडे–झंडियों से सजाया गया। एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया।

सरला हाल ही में पार्टी में शामिल हुई थीं और बड़ी ही सक्रिय थी। उन्होंने निरंजन सेन के साथ मिलकर एक सांस्कृतिक दल का गठन किया। सरला सम्मेलन की प्रिसीडियम में थीं उन्होंने सम्मेलन में महिला फ्रंट द्वारा खाद्य मोर्चे पर किए गए कार्य की रिपोर्ट पेश की।

सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान सरला ने एक कविता लिखी और उसका पाठ किया: ''लाल झंडा कहता है तुझसे पुकार, भैय्या मजदूरों!'' आगे वे सांस्कृतिक एवं महिला मोर्चो पर महत्वपूर्ण संगठनकर्ता बनीं।

उन्हें दिल्ली प्रादेशिक कमिटि (पी.सी.) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल किया गया. उनके साथ कमिटि में बहाल सिंह, वाई.डी. शर्मा, एम. फारूकी तथा मो. यामीन जैसे अग्रणी नेता शामिल थे। बाद में सरला दिल्ली पार्टी की कोषाध्यक्ष भी बनीं। आने वाले वर्षो में वे दिल्ली पार्टी के नेतृत्व में चुनी जाती रहीं।

महिला आंदोलन में

सरला 1940 में दिल्ली महिला लीग में शामिल हुई। महिला लीग ऑल इंडिया वीमेन्स कॉन्फ्रेंस (ए.आई.डब्ल्यू.सी.) का ही हिस्सा था। इसमें विभिन्न संगठन शामिल थे। वे लीग की संयुक्त सचिव चुनी गई। सरला ने 1942 के आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और चांदनी चौक में एक विशाल रैली में हिस्सा लिया। उन्होंने आंसू गैस झेलते हुए 'अंग्रेजों, भारत छोड़ो!' के नारे लगाए।

सरला ने दिल्ली की नर्सो को संगठित किया। विक्टोरिया वीमेन्स हॉस्पिटल की एक नर्स की डायरिया से मृत्यु हो गई। उसके समर्थन में हड़ताल संगठित की गयी। उन्होंने नर्सो की दयनीय स्थिति के विरोध में तथा उनकी वेतन–वृद्धि के लिए संघर्ष किया।

सरला द्वारा 1943 में बंबई में आयोजित इप्टा का सम्मेलन आयोजित किया गया। वे इसकी कार्यकारिणी में चुनी गई। उन्हें दिल्ली में इप्टा संगठित करने की जिम्मेदारी दी गई।

उन्होंने मिलों और फैक्टरियों तथा रेलवे, टेक्सटाइल, रिक्शावालों, ट्राम मजदूरों, इ. उद्योगों एवं तबकों में काम किया तथा उन्हें संगठित किया।

बंबई की कपिला खांडवाला के साथ मिलकर सरला ने दिल्ली की श्रमिक महिलाओं की एक रिपोर्ट तैयार की। इसे 1946 में अकोला (महाराष्ट्र) में आयोजित ए.आई.डब्ल्यू.सी. के सम्मेलन में पेश किया गया।

दिल्ली महिला संघ की स्थापना 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान की गई थी। इसकी स्थापना ए.आई.डब्ल्यू.सी. के साथ मतभेदों के बाद की गई। बेगम हाशमी दिल्ली महिला संघ की अध्यक्ष और सरला गुप्ता महासचिव बनाई गई। इसकी सदय संख्या 5,000 थी। महिला संघ ने बंगाल के अकाल–पीड़ितों के लिए सक्रिय कार्य किए। उसने इप्टा के साथ मिलकर यमुना घाट पर ग्यारह दिनों तक लगातार सुबह 5 बजे से रात दस बजे तक फंड इकट्ठा कि या। सरला याद किया करतीं कि कैसे एक दर्जन लड़के–लड़कियां यमुना घाट पर खड़े होकर गीत गाया करते। बड़ी संख्या में वहां महिलाएं स्नान तथा प्रार्थना किया करतीं। वहां सरला अपने साथियों के साथ गीत गाया करतीं: ''भूखा है बंगाल रे साथी, भूखा है बंगाल, सुनो हिंद के रहने वालों.....'' महिलाओं से वे एक–एक सिक्का उनकी झोली में डालने को कहती। सरला का ग्रुप घर–घर जाकर बंगाल के अकाल–राहत कोष के लिए फंड इकट्ठा किया करता। गांधी ग्राउंड में वे गीत–संगीत और नाटकों का आयोजन करतीं।

दिल्ली महिला संघ ने व्यापक तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वे लोग न सिर्फ सार्वजनिक स्थलों पर बल्कि घर के आंगन या पिछवाड़े में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम किया करतीं ताकि महिलाएं आसानी से देख सकें। महिलाओं ने कालाबाजारी और चोरबाजारी के खिलाफ आवाज उठाई। कई मौकों पर उन्होंने गोदामों में छिपाए गए अनाज भंडारों पर छापा भी मारा और सेठों को अनाज बेचने पर मजबूर कर दिया।

जब कलकत्ता पर जापानियों ने बम वर्षा की तो सरला ने रात–भर बैठकर एक ड्रामा लिखा। उसे 10 फरवरी 1943 को गांधी मैदान में 'तानिया' नाम से शैडो–प्ले के रूप में प्रस्तुत किया गया। 25 हजार से भी अधिक लोगों ने इसे देखा।

दिल्ली महिला संघ ने दरियागंज स्थित सरस्वती भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया। सरला ने गांधी मैदान में चित्रकारी की प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसका मुख्य विषय बंगाल का अकाल था। इसमें खुद अपनी पेंटिंग, अपने भाई

शेष पेज 14 पर...

अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन का राज्य सम्मेलन संपन्न

घर चौपाल से लेकर वैश्विक शांति पर हुआ चिंतन

इंदौरः अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन (एप्सो) का 15वां राज्य सम्मेलन इंदौर में संपन्न हुआ। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए अनेक प्रतिनिधियों ने घर, परिवार, चौपाल से लेकर विश्व में शांति के प्रयासों पर चिंतन– मनन किया। सम्मेलन में भारत में निरंतर बढ़ रही फासीवादी प्रवृत्तियों के प्रतिरोध हेतु संयुक्त पहल के लिए एप्सो से अनुरोध किया गया। सम्मेलन में अनेक प्रस्ताव पारित किए गए नई कार्यकारिणी का गठन भी हुआ। वक्ताओं ने गांधीजी की शहादत के 75 वर्ष पर शासन की चुप्पी पर सवाल उठाए।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद समाजवादी नेता कल्याण जैन ने नफरत भरे माहौल में शांति के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि विश्व की बहुसंख्यक आबादी अमन चाहती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पूंजीवादी साम्राज्यवादी देश राष्ट्रों के बीच विवादों को बढ़ावा देते हैं और हथियारों के व्यापार के माध्यम से मुनाफा कमाते हैं। दुनिया में वर्ण भेद, रंगभेद, भाषा, जाति के नाम पर भी विवाद हैं। हर तरह के अन्याय के खिलाफ अहिंसक लड़ाई की जरूरत है। देश में घृणा का बाजार लगा है, नफरत फैलाने वालों में प्रधानमंत्री तक शामिल हैं। दुनिया की समस्याओं का कारण आर्थिक असमानता है। देश में एक प्रतिशत आबादी के पास देश की आधी संपत्ति है। यही समस्याओं का मूल है।

अनूपपुर से आए विजेंद्र सोनी ने कहा कि व्यक्ति और समाज देश में शांति चाहते हैं। उन कारणों पर विचार करने की जरूरत है जिनके कारण अशांति पैदा होती है। राजनीति जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में राजनीतिक दृष्टि होना चाहिए। न्याय की आकांक्षा सदैव रही है। इसे प्रोत्साहित किये जाने की जरूरत है। देश में हिंसक प्रतीकों को माध्यम बनाकर डर फैलाया जा रहा है। पौराणिक कथाओं में से करुणा, दया, आपसी भाईचारे, प्रेम प्रसंगो के स्थान पर, उन घटनाओं को तरजीह दी जा रही है जो हिंसा के लिए उकसाते हैं। देश का मध्य वर्ग शांति का पक्षधर है। उसे अपने साथ जोड़ा जाना चाहिए।

भोपाल के प्रतिनिधि शैलेंद्र शैली ने अपने संबोधन में फासीवाद के प्रतिरोध हेतु व्यापक मोर्चा बनाने पर बल दिया। उन्होंने आग्रह किया कि एप्सो को इस हेतु पहल करना चाहिए। श्री शैली ने कहा की संगठन का फलक व्यापक है। विभिन्न मुद्दों के आधार पर कार्यकर्ताओं के लिए वैचारिक शिविर लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि संगठन को जन विरोधी गतिविधियों और नफरत की राजनीति का विरोध करना चाहिए।

पर्यावरणविद अरुण डीके ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म का सही विश्लेषण किया था। उसी को आगे बढ़ाकर महात्मा गांधी ने धर्म के मर्म से परिचय करवाया। गांधी की मशाल को विनोबाभावे आगे ले गए। जब तक देशवासी अन्य प्रादेशिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भारत एकजुट नहीं रह सकता।

गांधीवादी चिंतक वरिष्ठ अभिभाषक अनिल त्रिवेदी के अनुसार वर्तमान में शांति आंदोलन की सर्वाधिक आवश्यकता है। इस हेतु एप्सो संगठन और उसके विचारों को विस्तारित करने की जरूरत है। देश में राजनीति पर बात ही नहीं की जाती है। जबकि ख्यालात ही हालात को बदलते हैं।

हरनाम सिंह

देश में स्वतंत्र चिंतन को समाप्त करने के प्रयास हो रहे हैं। नागरिकों को रोबोट बनाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है। डराने वालों से डरने की जरूरत नहीं है। हमारी विरासत कायरता की नहीं शहादत की रही है। देश में दंगा करने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती लेकिन प्रेम विवाह के लिए अनुमति जरूरी है। प्रेम पर पहरा बिठा दिया गया है और नफरत सरेआम घूम रही है। वर्तमान पीढ़ी संचार साधनों और तकनीक के अनुरूप अपना जीवन गढ़ रही है। कॉरपोरेट संस्कृति पर विचार होना चाहिए। राज्य नाम की संस्था विलुप्त होती जा रही है अब राज्य का संचालन कारपोरेट कर रहे हैं। टेलीविजन और मोबाइल कंपनियों के बहिष्कार की जरूरत है।

संगठन के महासचिव अरविंद पोरवाल ने अपने प्रतिवेदन में विगत सम्मेलन पश्चात संगठन की गतिविधियों एवं आय–व्यय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नव–उपनिवेशवाद ने स्थाई शांति की उम्मीद को धाराशाही कर दिया है। दुनिया में असमानता, बेरोजगारी और गरीबी में अभूतपूर्व वृद्धि के चलते उत्पीड़ित लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। दुनिया के कई हिस्सों में भिन्न–भिन्न स्वरूपों में पूंजीवादी, फासीवादी सत्ता को चुनौती दी जा रही है। शांति एवं एकजुटता संगठन (एप्सो) मानव जाति की प्रगति और कल्याण में विश्वास करता है। देश में धर्मनिरपेक्ष विचारों की रक्षा की चुनौती है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए। सम्मेलन में विगत वर्षो में दिवंगत हो चुके संगठन के पदाधिकारियों, सदस्यों, लेखकों, रंगकर्मियों, साहित्यकारों, चित्रकारों की सेवाओं का स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

प्रस्ताव जो पारित हुए

सम्मेलन में महात्मा गांधी की शहादत के 75 वर्ष पूरे होने पर उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए विश्व शांति हेतु अनेक प्रस्ताव स्वीकार किए। फिलिस्तीन के नागरिकों द्वारा स्वतंत्रता एवं संप्रभु राष्ट्र की स्थापना हेतु चलाए जा रहे संघर्ष का समर्थन, यूक्रेन युद्ध और नाटो के विस्तार योजना का विरोध, ब्राजील में लोकतंत्र पर हमले की निंदा, लेटिन अमेरिका में साम्राज्यवादी दखल, यूरोप में ताकतवर होते दक्षिणपंथ, आर्थिक असमानता, भारत की विदेश नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सांप्रदायिक हमलों के विरोध पर तथा जलवायु संरक्षण पर प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किए गए।

सभा पटल पर प्रस्ताव रामस्वरूप मंत्री, कैलाश लिंबोदिया, विजय दलाल, अजीत केतकर, शैलेंद्र शैली, हरनाम सिंह, विवेक मेहता, राहुल भाई जी, अजय लागू, प्रमोद नामदेव, आशीष जैन ने रखे। इनके अलावा भारत सिंह ठाकुर ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, रामदेव सायडीवाल ने रोजगार, रूद्र पाल यादव ने संविधान बचाने, भोपाल के जेपीदुबे ने युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने, चुन्नीलाल वाधवानी ने देश के संघीय ढांचे पर हो रहे हमले पर चिंता व्यक्त की। सम्मेलन में सुशीला शिल्पी, सुषमा कौशल ने भी अपने विचार व्यक्त किए आभार माना अध्यक्षमंडल के श्री श्याम सुंदर यादव ने।

राज्य कार्यकारिणी का गठन

इस अवसर पर नई राज्य कार्यकारिणी का गठन किया गया।

आनंद मोहन माथुर, लज्जा शंकर हरदेनिया, कल्याण जैन, वसंत शिंत्रे, डॉ. भरत छापरवाल एवं अनिल त्रिवेदी संरक्षक मण्डल, श्याम सुन्दर यादव, रामबाबू अग्रवाल, दिलीप राजपाल, रामस्वरूप मंत्री, अरविन्द श्रीवास्तव, जसविंदर सिंह, मुकुंद कुलकर्णी, आलोक खरे, अध्यक्ष मण्डल, अरविन्द पोरवाल, इंदौर, शैलेन्द्र शैली, भोपाल, विजेंद्र सोनी, अनूपपुर महामंत्री एवं योगेंद्र माहवार कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इंदौर जिले की कार्यकारिणी में अरविन्द पोरवाल, सुनीलचंद्रन, अजित केतकर, विवेक मेहता, विजय दलाल, दिलीप जोशी महामंत्री निर्वाचित हुए।

निराशाजनक और खोखला है बजट 2023–24...

पेज 3 से जारी...

जमा की सीमा को बढ़ाकर महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों को राहत देने की बात कही गई है परन्तु यह किसी बड़े फायदे के रूप में नहीं बदलती। बढ़ती लिंग मजदूरी असमानता और घटती महिला रोजगार दर की समस्या का समाधान नहीं किया गया है। चुनिंदा मदों पर जीएसटी की छूट गैर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को ही घटाती है। जो आम आदमी अप्रत्यक्ष टैक्स देता है उसे कोई राहत नहीं दी गई। बजट में ''ईज ऑफ डूईंग बिजनेस'' (कारोबार करने को आसान बनाने) की बात की गई है। देखना होगा कि नियोक्ताओं को क्या फायदे पहुंचाये गये हैं। यह मजदूरों के हितों पर एक चोट होगी।

सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों की समस्याओं का पर्याप्त समाधान नहीं किया गया है। गारंटी बढ़ाने के तरीके से जो कुछ किया गया है यह इस विशाल क्षेत्र–जो विकास का इंजिन एवं रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है–के लिए अत्यंत मामूली सी बात है। बजट इस बारे में मौन है कि राजस्व कहां से पैदा होगा। अमीरों एवं कारपोरेटों पर टैक्स के जरिए टैक्स की आमदनी बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की गई है। इसमें और अधिक उधारी लेकर घाटे को पूरा करने की बात कही गई है। भारत पर कर्ज का बोझ पहले ही बहुत अधिक है और कर्ज के और अधिक बोझ से ब्याज अदायगी का बोझ बढ़ जायेगा।

बजट मानव एवं सामाजिक विकास को ऊपर उठाने में पूरी तरह विफल है। यह बढ़ती भूख, गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे को हल नहीं करता।

आरक्षण बचाओ, महंगाई हटाओ, रोजगार दिलाओ, भाजपा भगाओ अभियान

प्रदेश भर में धरने, प्रदर्शनों के साथ भाकपा का अभियान संपन्न

लखनऊ, 18 जनवरी 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यालय से पार्टी राज्य सचिवमंडल की ओर से राज्य सचिव अरविन्द राज स्वरूप ने बयान जारी करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में आरक्षण बचाओ, महंगाई हटाओ, रोजगार दिलाओ, भाजपा भगाओ के नारे पर एक सप्ताह चलाए गए अभियान के समापन पर धरने प्रदर्शन आयोजित किए गए और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रेषित किए गए।

सचिवमंडल की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से और 2017 से यूपी की डबल इंजन सरकार जब से बनी हुई है देश की और प्रदेश की जनता पर भारी मुसीबतें आई हुई हैं।

सरकार उन मुसीबतों से निपटने के लिए सिर्फ एक ही एजेंडा चलाती है और वह है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और उसका लाभ उठाकर बाकी जन विरोधी कार्य करती है।

विगत दिवस ऑक्सफैम की रिपोर्ट से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि भारत देश की 40 प्रतिशत दौलत देश के 1प्रतिशत धन्ना सेठों के हाथ में केंद्रित हो चुकी और यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आर्थिक नीतियों के ही कारण संभव हो सका है। इतना ही नहीं यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि जीएसटी में जो सरकार को प्राप्ति हुई है उसमें बड़े–बड़े धन्ना सेठों नें कुल 3 प्रतिशत टैक्स दिया है और बाकी 50 प्रतिशत गरीब जनता ने 64 प्रतिशत टैक्स की अदायगी की है। इस तथ्य से अधिक आंख खोलने वाली कोई बात होती नहीं है।

उक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि अमीरों के मुकाबले गरीब कहीं ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं, जीवन के लिए जरूरी चीजों पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, महंगाई की भी सबसे अधिक मार वही झेल रहे हैं। रिपोर्ट ने यह भी बताया की सभी अरबपतियों के पास जितनी संपत्ति है उस पर केवल एक बार के लिए 2 प्रतिशत टैक्स लगा दें तो तो 40423 करोड रुपए अर्जित होंगे जिससे भारत में 3 साल के लिए कुपोषितो को भोजन मिल पाएगा।

सचिवमंडल के बयान में कह कहा गया कि सरकार की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के कारण समाज में विषमता और गरीबी बढी है। सरकार और सरकार को चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी एवं आरएसएस की जोड़ी संविधान की भावनाओं को भी आहत कर रही है और इसीलिए वह इतिहास के पुनर्लेखन की बात करती है ताकि देश के नौजवानों को सच्चाई पता न लग जाए और राष्ट्रीयता की भी नई परिभाषा गढ़ रही है।

उत्तर प्रदेश में सरकार की नीतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे प्रदेश में पूरे 1 सप्ताह अभियान चलाया और 18 जनवरी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत किया।

ज्ञापन में रेखांकित किया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वंचितों को वंचित ही रखना चाहती है। इसीलिए आए दिन आरक्षण को समाप्त करने के बयान भाजपा आरएसएस जोड़ी की ओर से दिए जाते हैं और इसके लिए काम किया जाता है। नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि 2021 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आने के पश्चात भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने निकाय चुनाव में उन आदेशों के अनुसार आरक्षण नहीं किया और चुनाव को अदालतों में फंसा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आरक्षण की कार्यवाही की जाए और उसके लिए जो जरूरी है वह किया जाए।

उसी तरह से महंगाई को भी यह सरकार रोकना नहीं चाहती है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्रूड ऑयल के दाम स्थिर होने के बावजूद भी प्रत्येक नर नारी को पेट्रोल और डीजल के भारी दाम देने पड़ रहे हैं और सरकार कोई भी रियायत नहीं कर रही है और ऐसा ही खाने की गैस के साथ हो रहा है।

सरकार जनता को लूट कर अपनी तिजोरिया भर रही है ताकि वह मनमानी कर सके और देश के संसाधनों को बड़े बड़े धन्ना सेठों को सौंप सकें। इसी कारण से उन संस्थानों में नौकरियां समाप्त होती जा रही हैं जो नौजवानों को नौकरियां प्रदान करते थे और वह एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, के लिए आशान्वित होते थे।

सरकार इन प्रमुख मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए बड़ी चालाकी से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, राष्ट्रवाद, चीन, पाकिस्तान, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन आदि मुद्दे लाती है। बयान में यह भी नोट किया गया कि जनता अब धीरे–धीरे इन समस्याओं को समझती जा रही है और यह सकारात्मक सामाजिक बात है कि अभी हाल में हुए इलेक्शंस में सिर्फ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीती है। हिमाचल में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी और खतौली में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारी है। भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वालों ने उसका साथ छोड़ कर दूसरे दलों को वोट किया है। रामपुर की सीट में तो चुनावी धांधली हुई है जिसकी शिकायत प्रत्याशी गण पहले से ही कर रहे थे। मुख्य बात है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हारने का कारण उसकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नीतियां ही हैं।

राज्य केंद्र को प्राप्त सूचना के अनुसार आज 1 सप्ताह के अभियान के समापन के पश्चात विभिन्न जिलों में धरना प्रदर्शन करके महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सौंपा गया।

महामहिम राष्ट्रपति जी को सौपे गए ज्ञापन में मांग की गई है और कहा गया है कि आरक्षण बचाओः भारत का संविधान जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किसी भी वर्ग में भेद नहीं करता है। लेकिन आज कल जाति, धर्म, लिंग और भाषा के आधार पर ही बीजेपी/आरएसएस की सत्ताधारी सरकार आदमी–आदमी और महिला–महिला के बीच खाई बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में दिन रात जुटी है।

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की रिजर्वेशन विरोधी नीति स्पष्ट हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट का 2021 का फैसला था तो उसके आधार पर ओबीसी जातियों का सर्वे क्यों नहीं करवाया गया?

यह अपने में बड़ा प्रश्न है! तथा बीजेपी का पर्दाफाश करता है।

भारतीय जनता पार्टी, इनके नेतागण और स्वयं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रिजर्वेशन को ही समाप्त करवा देना चाहते हैं और संविधान और देश के कानून नें जो हजारों साल वंचित रहे लोगों को स्थान दिया था उसको छीन लेना चाहते हैं।

बेरोजगारीः आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा चाहे केंद्र हो ,चाहे उत्तर प्रदेश, कारखाने बंद किए जा रहे हैं या उनको प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा रहा है। जिनमें निरंतर रोजगार कम हो रहा है। यहां तक कि लाखों वैकेंसी सरकारी विभागों में है और उनको भी भरा नहीं जा रहा है।

जो कुछ थोड़ा बहुत एंप्लॉयमेंट है, जो नौकरी मिल रही है वह ठेके पर दी जा रही है और जिस पर वेतन जीनें लायक नहीं है। जनता को अपार कष्टों में रखा जा रहा है और बेरोजगार नौजवान घर घर बैठा है।

मोदी ने 2 करोड रोजगार नौजवानों को देने का प्रतिवर्ष वायदा किया था। परंतु वह वायदा वायदा ही रह गया। कभी पूरा नहीं हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर जो श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है में 2022 –23 में 1.42 करोड़ लोगों ने नौकरी पाने के लिए अपने को रजिस्टर किया था। उस काल में जो वैकेंसी थी वह उस पोर्टल पर 71447 दिखाई गई थी। तो स्वयं सरकार का यह आंकड़ा कितनी घनघोर कठिन रोजगार की स्थिति है को प्रदर्शित करता है।

बेरोजगारी के आंकड़े से ही आजीविका संकट का संपूर्ण परिदृश्य स्पष्ट नहीं होता। इसकी वास्तविक स्थिति श्रम भागीदारी दर और लोगों की आय से समझी जा सकती है। नीति

शेष पेज 12 पर...

श्रमिकों का राष्ट्रीय सम्मेलन, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एनेक्सी 30 जनवरी, 2023, नई दिल्ली

हमारे देश के मेहनतकश लोगों के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र क्षेत्रीय राष्ट्रीय संघों/एसोसिएशनों के संयुक्त मंच के आह्वान पर 30 जनवरी, महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित होने वाले श्रमिकों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियों के कारण हमारे देश में श्रमिकों और आम लोगों के सभी वर्गों के सामने उत्पन्न चिंताजनक स्थिति का संज्ञान लिया गया। ये नीतियां, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, न केवल मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी हैं, बल्कि राष्ट्रविरोधी भी हैं। वे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए विनाशकारी साबित हुई हैं। इन विनाशकारी नीतियों से 'देश को बचाने और लोगों को बचाने' के आगामी कल की संयुक्त कार्रवाई को तय करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

हम, जो यहां एकत्र हुए हैं, हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों के श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं: संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र और उद्योग, सेवाओं और बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र हम निर्माण श्रमिकों, जलविद्युत और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में लगे श्रमिकों, योजना श्रमिकों, बीड़ी श्रमिकों, तेंदू पत्ता उत्पादकों, अनुबंध श्रमिकों, लोडिंग और अनलोडिंग श्रमिकों, अन्वेषण, निष्कर्षण और तेल के परिवहन में लगे श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। गैस, कोयले की खदानों में काम करने वाले और विभिन्न अन्य खानों में लगे कामगार, मतस्य क्षेत्र में काम करने वाले, रेहड़ी–पटरी लगाने वाले, घरेलू कामगार, घर पर काम करने वाले कामगार, कालीन बुनाई, आतिशबाजी, बागान, कृषि और बागवानी में काम करने वाले कामगार, गिग कर्मचारी, आईटी और आईटीईएस कर्मचारी, बैंक और बीमा कर्मचारी, राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी, दूरसंचार और डाक कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, बंदरगाह और गोदी कर्मचारी, सड़क, जल, वायु और रेलवे सहित परिवहन कर्मचारी, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र के कर्मचारी, सरकारी प्रेस से और कई अन्य क्षेत्रों से अनुसूचित और अनिर्धारित श्रेणियों में कार्यरत लोग। हम कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में लगे लोगों और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि में काम करने वालों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं और 2014 के बाद से भाजपा शासन के 8 से अधिक वर्षों का जायजा लेते हैं, तो यह लोगों के जीवन और आजीविका पर सरकार द्वारा संचालित हमले की तस्वीर प्रस्तुत करता है और आम लोगों के बड़े हिस्से के अकल्पनीय दुख, संकट और विनाशका कारक नज़र आता है। नौकरी छूटना और बेरोजगारी बेरोकटोक बढ़ रही है। इसकी शुरुआत विमुद्रीकरण से हुई, जिसके परिणामस्वरूप आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा। सरकार को इस पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। गरीबी ने और अधिक आर्थिक मंदी को कायम रखा है। यह बदले में नौकरी के नुकसान और विशेष रूप से युवाओं के बीच बेरोजगारी की स्थिति को और बढ़ा रहा है। निरंतर मूल्य वृद्धि और घटती वास्तविक मजदूरी ने आम जनता के दुखों में बढ़ोतरी की है और भूख सूचकांक में गिरावट आई है। हमने अपने मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन, संगठित क्षेत्रीय और अखिल भारतीय हड़तालें की हैं, लेकिन यह मौजूदा सरकार लोगों की चिंताओं के प्रति पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है।

क्या हम कह सकते हैं कि सरकार ने कोई संज्ञान लिया है? न केवल कोई संज्ञान लिया गया है, बल्कि सरकार अहंकारपूर्वक और आक्रामक रूप से उन्हीं नीतियों को अपना रही है।

हमें इस बात की चिंता है कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन सरकारी रिक्तियों को भी नहीं भरा जाता है, जो उनके अधिकार में है। कई सार्वजनिक उपक्रमों को बंद किया जा रहा है या निजी पार्टियों को बेच दिया जा रहा है, जो तुरंत "डाउन–साइज़िंग" शुरू करते हैं, कई हज़ार श्रमिकों को रोज़गार से बाहर कर देते हैं। ठेका कर्मचारी नौकरी छूटने और छंटनी के प्रमुख शिकार बन गए हैं। सरकार में कार्यरत कोविड से लड़ने वाले अस्पतालों में नियुक्त स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी को भी, स्थायी करने के वादे के बाद भी अब नौकरी से निकाला जा रहा है। कोविड के बाद भी जब जीवन को पटरी पर लाने के लिए नौकरियों की सख्त जरूरत है, अवैध तरीके से भी फैक्ट्रियों को बंद होने दिया जा रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा हो रही है। हम मांग करते हैं कि मनरेगा को साल में 200 दिनों तक बढ़ाया जाए और पारिश्रमिक में वृद्धि की जाए और इसी तरह की योजना शहरी क्षेत्रों में भी लाई जाए। लेकिन सरकार ने बजटीय आवंटन में भारी कमी की है; कार्य दिवसों की संख्या प्रति वर्ष 50 दिनों से भी कम हो गई है; कम किया गया आवंटन भी अप्रयुक्त लौटा दिया जाता है। लगभग सभी कल्याणकारी योजनाओं और लोगों से संबंधित परियोजनाओं में बजटीय आवंटन में भारी कटौती की गई है।

हम मांग करते हैं कि योजना कर्मियों को आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन के साथ सरकारी पदों पर स्थायी किया जाए।लेकिन सरकार उन पर फूल बरसाने के अलावा और कुछ नहीं देती। यह और कुछ नहीं बल्कि कोविड महामारी के दौरान उनके अनुकरणीय

घोषणा

कार्य पर एक क्रूर मजाक है।

घर पर काम करने वाले 3.5 करोड़ कार्यबल और अपशिष्ट पुनर्चक्रण कार्य में लगे श्रमिकों, घरेलू कामगारों को सुरक्षा के साथ–साथ सामाजिक सुरक्षा की भी आवश्यकता है। प्रवासी श्रमिकों के लिए राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा लाभों में पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए। कल्याण बोर्डों के अंतर्गत आने वाले निर्माण और बीड़ी श्रमिकों और इसी तरह के अन्य श्रमिकों के मैनुअल पंजीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए।

हम ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत उन सभी 28 करोड़ असंगठित श्रमिकों के बच्चों के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा, जीवन और विकलांगता, बाल देखभाल, मातृत्व और शिक्षा पर सामाजिक सुरक्षा योजना के तत्काल ढांचे की मांग करते हैं। हम सार्वभौमिक सरकारी वित्त पोषित सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं की मांग करते हैं और प्रतिगामी बाजार संचालित नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को खत्म करने और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग करते हैं। लेकिन सरकार उलटी दिशा में चल रही है; वित्त मंत्री ने अहंकारवश एनपीएस को खत्म करने से इनकार कर दिया। हम ओपीएस की बहाली के लिए विभिन्न मंचों के आंदोलन के लिए अपना समर्थन और एकजुटता व्यक्त करते हैं। हम ईपीएस 95 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने और ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 8000 रुपये प्रति माह करने की मांग करते हैं। हम बड़े पैमाने पर चल रहे ठेकाकरण और उद्योगों में नियमित और बारहमासी काम के आकस्मिककरण को रोकने की मांग करते हैं; हम नियमित श्रमिकों के समान काम करने वाले अनुबंधित/अस्थायी/आउटसोर्स श्रमिकों के लिए समान वेतन और लाभ की मांग करते हैं। लेकिन कार्पोरेट नियंत्रित सरकार विभिन्न माध्यमों से नियमित/स्थायी कार्य के ठेकाकरण को कानूनी और वैध बनाने की कोशिश कर रही है।

हम सार्वजनिक उपक्रमों, आयुध कारखानों, विभागीय उपक्रमों के निजीकरण को रोकने और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन को खत्म करने की मांग करते हैं। लेकिन सरकार ने एयर इंडिया, पवन हंस, हवाई अड्डों को बेच दिया है; रेलवे की उत्पादन इकाइयों के निजीकरण की प्रक्रिया; नियमित प्रकृति, नियमित गतिविधियों के 60 प्रतिशत से अधिक की आउटसोर्सिंग; हाल ही में रेलवे में अनुबंध अवधि के लिए तकनीकी पर्यवेक्षकों, सेक्शन इंजीनियरों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने की घोषणा की और निजी क्षेत्र में 150 वंदे भारत ट्रेनों के लिए पहले ही घोषणा की; नीलामी/मुद्रीकरण आदि के लिए कोयले में 500 ब्लॉकों की पहचान की गई। सरकार बेशर्मी से घोषणा करती है, "हम जो कुछ भी बेच सकते हैं और यहां तक कि जो नहीं बेचा जा सकता है, हम बेच देंगे"। क्या यह हमारे घावों पर नमक छिड़कना नहीं है? क्या इससे बड़ा भी अहंकार हो सकता है?

हम अपने बच्चों के लिए अच्छी और सस्ती शिक्षा चाहते हैं; लेकिन नई शिक्षा नीति लाई गई है, जो निषेधात्मक लागतों के माध्यम से हमारे बच्चों को शिक्षित करने के अवसरों को छीन लेगी। बड़ी संख्या में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, विशेष रूप से प्राथमिक और माध्यमिक स्तर में, कर्मचारियों की भारी कमी है। विचार यह है कि सार्वजनिक शिक्षा को उसके बुनियादी ढांचे के साथ पूरी तरह से निजी शिक्षा व्यवसाय को सौंप दिया जाए। इसके अलावा, सांप्रदायिक संगठनों की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रम को बदलकर पाठ्यक्रम को विकृत किया जा रहा है।

हमने चार श्रम संहिताओं का पुरजोर विरोध किया है; इसके बजाय हमने बढ़ते आर्थिक संकट और कार्यस्थलों पर इसके प्रभाव को देखते हुए श्रम अधिकारों के विस्तार की मांग की। हमारे विरोध को पूरी तरह दरकिनार करते हुए, सरकार ने अपने कॉर्पोरेट आकाओं को संतुष्ट करने के लिए श्रमिकों को दास जैसी स्थितियों में धकेलने के लिए श्रम संहिताएँ लागू कीं। हालाँकि, यह एक तथ्य है कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर और साथ ही कार्यस्थलों पर निरंतर प्रतिरोध किया, श्रम संहिताओं को अभी तक आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया जा सका है। लेकिन जब तक उन्हें खत्म नहीं किया जाता, उन्हें किसी भी समय अधिसूचित किया जा सकता है।

किसानों ने कभी भी तीन कृषि कानूनों की मांग नहीं की। मजदूर वर्ग के समर्थन से अपने ऐतिहासिक संघर्ष के जरिए उन्होंने तीन कृषि कानूनों का विरोध किया है। कृषि कानूनों को वापस लिया गया, लेकिन यह एक चाल थी, जो अब तक स्पष्ट हो चुकी है। एमएसपी और खरीद पर प्रतिबद्धता को लागू नहीं किया गया है।

2015 के बाद से आयोजित नहीं किए गए त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन की मांग, जिसे आईएलओ कन्वेंशन 144 के अनुसार अनिवार्य रूप से हर साल कम से कम एक बार आयोजित किया जाना चाहिए, को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। कार्यस्थल पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों पर आईएलओ घोषणा, ै्भ को शामिल करने के लिए हालिया संकल्प और मौलिक अधिकारों के रूप में कार्यस्थल पर सुरक्षा का कोई संबंध नहीं है। हम आईएलओ (प्स्व) कन्वेंशन 87,98,189,190 के अनुसमर्थन की मांग कर रहे हैं। इसके बजाय केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की "वन–टू–वन" बैठकें श्रम मंत्री के साथ आयोजित की जाती हैं, जहाँ वे "श्रम सुधार" को आक्रामक रूप से अपने समर्थक कॉर्पोरेट एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। संयुक्त मजदूर वर्ग आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर और कार्यस्थल दोनों स्तरों पर संयुक्त कार्रवाई के माध्यम से इस तरह की साजिश का डटकर मुकाबला करना होगा।

हम मांग करते हैं कि नवउदारवादी

व्यवस्था के प्रणालीगत संकट के दोष से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए वैधानिक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि और सरकारी वित्त पोषण और ऐसे अन्य उपायों के साथ सामाजिक सुरक्षा उपायों को सार्वभौमिक बनाने और उनके विस्तार के जरिए आम लोगों के हाथों में अधिक पैसा देने की मांग करते हैं। यही लोग हमारी राष्ट्रीय संपत्ति बनाते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चालू रखते हैं। यह कॉर्पोरेट्स, अमीरों और सुपर रिच पर टैक्स बढ़ाकर, वेल्थ टैक्स और सक्सेशन टैक्स को बहाल करके किया जा सकता है। इसके बजाय सरकार डिजिटल मुद्रा का विचार लेकर आई है जो अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है।

हम जीएसटी/अप्रत्यक्ष करों में कमी की मांग करते हैं, विशेष रूप से भोजन, दवाओं और आवश्यक सार्वजनिक उपयोगिताओं सहित आवश्यक वस्तुओं पर जो आम लोगों पर एक असहनीय बोझ बन गए हैं। लेकिन सरकार घरेलू और विदेशी बड़े कॉर्पोरेट्स के हितों के लिए पूरी तरह से गुलाम है, और मुट्ठी भर सुपर रिच कॉर्पोरेट्स के टैक्स को कम करते हैं और जीएसटी/अप्रत्यक्ष करों को बढ़ाते हैं!! इसके अलावा हम मांग करते हैं कि कल्याणकारी योजनाओं पर जीएसटी को खत्म किया जाए।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की निरंतर मंदी, देश के औद्योगिक आधार का विऔद्योगीकरण और विनाश, एमएसएमई का विनाश, आत्मनिर्भरता का नुकसान, हमारे साथ–साथ हमारे लोगों के भारी बहुमत पर बोझ बढ़ रहा है। एक तरफ बड़े कॉर्पोरेट वर्ग की दौलत और आय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और मेहनतकश जनता की दरिद्रता बढ़ी है। जनता के साथ–साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की लूट–खसोट को बढ़ावा देने वाली शासन की पूरी व्यवस्था का पर्दाफाश हो गया है।

परिणाम भारत में आय की चरम और अश्लील असमानता है: भारत में शीर्ष 10 प्रतिशत और शीर्ष 1 प्रतिशत क्रमशः कुल राष्ट्रीय आय का 72 प्रतिशत और 40.5 प्रतिशत है, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत का हिस्सा घटकर मात्र 3 प्रतिशत रह गया है। परिणामी प्रभाव जनता की व्यापक दरिद्रता की खतरनाक घटना रही है। महामारी से पहले अरबपति 100 थे जबकि अब बढ़कर 166 हो गए हैं। सिर्फ 21 भारतीय अरबपतियों के पास इतनी बड़ी संपत्ति है, जो 70 प्रतिशत आबादी के पास है। दूसरी ओर भारत भूख, गरीबी, बच्चों की देखभाल, महिला सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार आदि सभी सूचकांकों में गिर रहा है।

लेकिन इससे भी अधिक अशुभ हो रहा है: यह केंद्र की सरकार और इसी पार्टी की अन्य राज्य सरकारें लूट और लूट के अपने शासन को बनाए रखने के लिए लव जिहाद, सीएए, एनआरसी जैसे मुद्दों को उठाकर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए अति सक्रिय हैं। उनके ज्वलंत मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मजदूरों और लोगों को बांटते हैं और कारपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए एकजुट संघर्षों को कमजोर करते हैं। यह कारपोरेट के स्वामित्व वाली मुख्यधारा की मीडिया के सक्रिय सहयोग से किया जा रहा है।

ईडी, सीबीआई, एनआईए, यूएपीए आदि जैसी सरकारी एजेंसियों की मदद से इस सरकार की आलोचना करने के लिए लेखकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्ष के सदस्यों को केवल तुच्छ आधार पर निशाना बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य आतंक का वातावरण तैयार कर, सभी विरोधों और असहमति को शांत करना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को तोड़ना है।

क्या यह सरकार पूरी तरह से हम जो चाहते हैं उसके खिलाफ नहीं है? हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वे जो कुछ भी करते हैं, वह विशाल कार्यबल की कीमत पर कॉर्पोरेट वर्ग और अमीर लोगों के लाभ के लिए है। यह सत्तारूढ़ व्यवस्था न केवल श्रमिकों, किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों, बुद्धिजीवियों आदि के हितों के खिलाफ काम कर रही है, बल्कि इसकी नीतियां कॉर्पोरेट भारतीय और विदेशी ब्रांड द्वारा प्राकृतिक संसाधनों और राष्ट्रीय संपत्ति की लूट की सुविधा भी दे रही हैं। ये नीतियां राष्ट्रहित के खिलाफ हैं।

इस जन–विरोधी, देश–विरोधी विनाशकारी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर मजदूर वर्ग के एकजुट आंदोलनों द्वारा निरंतर एकजुट हस्तक्षेप और संघर्ष सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यह साबित करते हुए कि इस विनाशकारी शासन का मुकाबला किया जा सकता है। हमारे संयुक्त संघर्षों के माध्यम से, बीपीसीएल, सीईएल, कुछ इस्पात संयंत्रों आदि जैसे कई सार्वजनिक उपक्रमों में निजीकरण की प्रक्रिया को रोका जा सका है, हालांकि कुछ समय के लिए। ताजा मामला महाराष्ट्र के बिजली कर्मचारियों का एकजुट संघर्ष है, जहां महाराष्ट्र सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले, जम्मू–कश्मीर, चंडीगढ़, यूपी, हरियाणा और पुडुचेरी में पिछले डेढ़ साल के दौरान बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ जुझारू संघर्ष के माध्यम से इसी तरह की सफलता हासिल की जा सकी है। निजीकरण के खिलाफ विशाखापत्तनम इस्पात के श्रमिकों का संघर्ष जारी है। अपने जुझारू संयुक्त संघर्षों के माध्यम से, विभिन्न राज्यों में योजना श्रमिकों ने अपने पारिश्रमिक में वृद्धि सहित अपनी कई मांगों को हासिल किया।

जरूरत इस बात की है कि श्रमिकों और लोगों को जागरूक किया जाए कि उनका असली दुश्मन, उनके दुखों और राष्ट्र के दुखों का कारण, केंद्र में कॉर्पोरेट द्वारा संचालित सरकार द्वारा संचालित राष्ट्र–विरोधी विनाशकारी नीति शासन है। उन्हें इन विनाशकारी नीतियों को बदलना होगा अन्यथा निष्कासन का सामना करना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर लोगों के साथ फ्रंटलाइन से नेतृत्व करते हुए इस कार्य का निर्वहन करना मजदूर वर्ग के आंदोलन की नियति है। अगले साल आम चुनाव से पहले साल 2023 सबसे अहम है।

यह एक महान कार्य है जिसके लिए हममें से प्रत्येक को अपने सामान्य अनुभव को आम जनता के लिए एक संदेश में बदलने के लिए अथक प्रयास करने की आवश्यकता होगी, जो सत्ता में उन लोगों के खिलाफ ज्वार को मोड़ने के लिए है जो राष्ट्र और इसके लोगों को अभूतपूर्व संकट और विनाश में धकेल रहे हैं।

एकजुट संघर्षों के हमारे पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, मजदूरों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन, हमारे देश के मेहनतकश लोगों से एकजुट संघर्षों को उच्च स्तर तक ले जाने का आह्वान करता है। हमें इस सरकार की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपनी लड़ाई तेज करनी होगी। 2023 का पूरा वर्ष सभी स्तरों पर संघर्ष के उच्च रूपों में परिणत होने के लिए एकजुट अभियानों और आंदोलनों का वर्ष होना चाहिए।

मजदूरों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन, अपनी 14 सूत्री मांगों के चार्टर को दोहराते हुए, जो नवउदारवादी नीति व्यवस्था के संपूर्ण सरगम के विकल्प को प्रोजेक्ट करता है, इस दिशा में काम करने का संकल्प लेता है और निम्नलिखित कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रस्ताव करता है:

– मार्च 2023 से मई 2023 तक का महीना राज्य/जिला/और क्षेत्रीय सम्मेलनों के आयोजन के लिए समर्पित होना चाहिए।

– जत्था कार्यक्रम: जून महीने से पदयात्रा/जीप जत्थे/साइकिल जत्थे/मोटरबाइक जत्थे आदि को किया जाना चाहिए। ऐसा कार्यक्रम राज्य सम्मेलनों में तय किया जाना चाहिए।

– जत्था कार्यक्रमों के माध्यम से ये जन अभियान 09 अगस्त को 'भारत छोड़ो दिवस' से राज्य–स्तरीय महापड़ाव में परिणत होंगे। संयुक्त राज्य सम्मेलनों के निर्णय के अनुसार यह कई दिनों का कार्यक्रम भी हो सकता है।

– हड़ताल की कार्रवाइयों सहित क्षेत्रीय संघर्षों का समर्थन और सहयोग किया जाना है।

– दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के दौरान मजबूत हुई मजदूर किसान एकता को और आगे ले जाने की जरूरत है। इस वर्ष कुछ संयुक्त कार्यक्रम किए जाएंगे।

वर्ष के अंत में देशव्यापी हड़ताल की कार्रवाई की ओर बढ़ने के लिए आंदोलन कार्यक्रमों को और तेज करने के लिए महापड़ाव

कार्यक्रम के बाद की गतिविधियों की समीक्षा की जानी चाहिए।

इंटक , एटक , एचएमएस , सीटू , एआईयूटक, टीयूसीसी , सेवा, एआईसीसीटीयू, एलपीएफ़, यूटीयूसी और स्वतंत्र राष्ट्रीय क्षेत्रीय संघ/एसोसिएशन।

एटक ने हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के मद्देनजर अडानी की जांच की मांग की

एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन में, एक निवेश अनुसंधान फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर एक शोध रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें दावा किया गया है कि यह समूह 'दशकों के दौरान बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी योजना' में लगा हुआ है। सबूत पेश करते हुए रिपोर्ट कहती है कि अडानी कांग्लोमरेट की सात लिस्टेड कंपनियों का वैल्यूएशन 85 प्रतिशत ज्यादा है।

हिंडनबर्ग शोध की रिपोर्ट गंभीर प्रकृति की है। यह रिपोर्ट अकाउंटिंग फ्रॉड और स्टॉक मैनिपुलेशन के पुख्ता सबूतों के साथ सामने आई है। यह आरोप लगाया गया है कि बढ़ा हुआ स्टॉक मूल्य बैंकों के पास ऋण लेने के लिए गिरवी रखा जाता है। रिपोर्ट में अडानी समूह से जुड़ी अपतटीय संस्थाओं और शेल

संस्थाओं के एक जटिल जाल की जांच करने का भी दावा किया गया है। यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो इसमें शामिल शेयरों के आकार को देखते हुए प्रभाव बहुत गंभीर होंगे।

रिपोर्ट किए गए स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी, अगर सही साबित होते हैं, तो इसमें सरकार और उसके विभागों का समर्थन और मिलीभगत शामिल होगी। रिपोर्ट में भारत के पूंजी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय नियामक निकाय की भूमिका की भी जांच की गई है।

वर्ष 2021–22 में गौतम अडानी की उल्कापिंड वृद्धि हुई, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी में थी, इस रिपोर्ट की पृष्ठभूमि छूटे बिना नहीं रह सकती। पूरी घटना इस सच्चाई को उजागर करती है कि कैसे क्रोनी कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से लूटता है। यह उदाहरण देने के लिए एक उत्कृष्ट मामला है कि कैसे प्रधानमंत्री और सरकार के मित्रों की किस्मत सरकार द्वारा नियंत्रित संसाधनों और विभागों तक पहुंच पर निर्भर करती है।

बिना आग के धुआं नहीं हो सकता। इस तरह की गंभीर धोखाधड़ी और जोड़–तोड़ की रिपोर्ट, जो शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर भारी प्रभाव डालेगी, को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

यह बताया जा रहा है कि अडानी के गिरते शेयरों को बचाने के लिए बेताब प्रयास किए जा रहे हैं और एलआईसी ऑफ इंडिया ने उन शेयरों को खरीदने की 'पेशकश' की है। सत्ता पर बैठे लोगों की मिलीभगत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। यह आम लोगों की कीमत पर अच्छे पैसे को खराब पैसे के बाद फेंकना है।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के मद्देनजर अडानी समूह की जांच की मांग की।

चुनी हुई सरकार बेहतर है नियुक्त राज्यपाल से

हरीश बाला

राज्यों में एक बार फिर राज्यपाल के पदों की जरूरत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। गैर–भाजपा शासित राज्यों में इस बहस में तेजी आई है। गैर–भाजपा शासित राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपाल भाजपा के एजेंटों के जैसे काम कर रहे हैं। वे न केवल चुनी हुई सरकारों के रोजमर्रा के कामकाज में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते है बल्कि आरएसएस के वैचारिक प्रचारक के रूप में भी काम करते हैं।

हाल की कई घटनाएं उक्त कथनों को साबित करती हैं। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और अन्य गैर–भाजपा शासित राज्यों में जनता की इच्छाओं और जनादेश के खिलाफ काम हो रहा है।

औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश राजशाही की शर्तों पर देश के प्रशासन के लिए भारत के कई प्रांतों में राज्यपाल के पदों को तैयार किया गया था। 1857 में भारत की आजादी के लिए हुई पहली लड़ाई के कारण 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के इलाके और परिसंपत्ति सीधे ब्रिटिश राज के नियंत्रण में आ गए थे। परणिामस्वरूप, भारत में कंपनी राज की जगह ब्रिटिश राज ने ले ली थी। गवर्नर–जनरल, जिसे वायसराय के पद से भी जाना जाता था, भारत के केंद्रीय सरकार का कार्यभार देखते थे। इसके तहत गवर्नर–जनरल पंजाब, बंगाल, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांतों और अन्य प्रांतों समेत ब्रिटिश भारत के प्रांतों से शासन चलाते थे। उन्होंने प्रत्येक प्रांत के लिए राज्यपाल नियुक्त किए थे। ये राज्यपाल सीधे गवर्नर–जनरल को रिपोर्ट करते थे।

1935 के भारत सरकार कानून ने प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म कर दिया था और ब्रिटिश सरकार की स्वायत्तता बढ़ा दी थी। उस समय छह प्रांतों को द्विसदन विधान सभाएं दी गई थी। पृथक निर्वाचक–मंडल पर आधारित चुनाव 1937 और 1946 में हुए थे, जिसके तहत प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ था जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता था। प्रांतीय विधानसभाओं के निर्णयों पर प्रत्येक राज्यपाल हावी रहते थे और स्वायत्तता का इस्तेमाल वास्तव में नहीं होता था, प्रांतीय विधानसभाओं की स्वायत्तता नाम भर के लिए थी। राज्यपालों का प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण रहता था।

मौजूदा भाजपा नीत केंद्रीय सरकार प्रत्येक राज्य में ब्रिटिश शासन के कामकाज की पद्धति को लागू करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट में2019 में राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हुआ था। 2019 में शिवसेना और भाजपा का गठबंधन था लेकिन उस समय भाजपा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के पद पर झगड़े के कारण सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं थी। उस समय किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं था, तब पार्टियों के बीच सरकार बनाने के लिए गठजोड़ की संभावनाएं तलाशते हुए बातचीत चली थी। उस समय महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी ने राजभवन में सुबह छह बजे सुरक्षाबंद समारोह में मुख्यमंत्री के रूप में देवेन्द्र फड़नवीस और अजीत पवार को उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई थी, इसके कारण महाराष्ट्र में तमाम राजनीतिक दलों के बीच एक राजनीतिक हड़कंप मच गया था। महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल ने विधायकों की खरीद–फरोख्त के लिए दरवाजा खोल दिया था। लेकिन सौभाग्यवश, विपक्षी दल सरकार बनाने के लिए एकजुट हो गए थे और देवेन्द्र फड़नवीस की सरकार कुछ दिन ही टिकी।

इसी तरह से कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस और जनता दल (स) ने चुनाव के बाद गठबंधन किया और तत्कालीन राज्यपाल विजुभाई वाला से सरकार बनाने के लिए बात की थी। विजुभाई वाला ने कर्नाटक की जनता के जनादेश का अनादर करते हुए इसकी बजाय भजापा के येदुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था।

येदुरप्पा को शपथ दिलाई गई। कांग्रेस और जनता दल(स) के विधायकों को ऑपरेशन कमला से तोड़ने में असफलता के बाद येदुरप्पा ने सदन मे बहुमत साबित न कर पाने के डर से चार दिनों में ही इस्तीफ दे दिया था।

हाल में केरल और तमिलनाडु में क्रमशः वाम जनतांत्रिक मोर्चा और द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम की निर्वाचित सरकार और राज्य पाल आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल आर.एन.रवि की गुत्थमगुत्था मुख्यतः वैचारिक है।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहमद खान ने केरल सरकार शासित विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद के लिए केरल सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों को हटाकर भाजपा समर्थकों को कुलपति बनाया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुलपतियों की नियुक्ति राज्य सरकार की सिफारिशों पर किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की सिफारिशों से अलग काम करना राज्य की उस जनता की आकांक्षाओं के खिलाफ है जिसने राज्य सरकार को चुना है।

वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने इसके जवाब में राज्यपाल को राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति पद से हटाने के लिए केरल विधानसभा में एक आर्डिनेंस लाई। इस ऑर्डिनेंस को राज्यपाल ने अनुमोदित नहीं किया। राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रीय सेवक संघ के एजेंडे और विचारधारा के प्रचारकों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारकों को नियुक्त करने की कोशिश कर रही है जिस राज्य ने नई शिक्षा नीति (नेप) को खारिज कर दिया है।

तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि का रोज का काम है विवादास्पद मुद्दों को भड़काना। जब तमिलनाडु विधानसभा ने इन्टरनेट पर चलनेवाले जुआ ऐप्स को गैर–कानूनी बनाने के लिए एक विधेयक पास किया तो राज्यपाल ने इस विधेयक को अनुमोदित नहीं किया। राज्यपाल ने न तो यह विधेयक दोबारा तमिलनाडु सरकार को भेजा, इस तरह से राज्यपाल ने इस विधेयक को नामंजूर कर दिया।

ऑनलाइन जुआ (गेम्बलिंग) ऐप्स से वित्तीय कठिनाइयों में फंसे कई युवकों ने आत्महत्या की। तमिलनाडु की निर्वाचित सरकार ने जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरह की गेम्बलिंग ऐप्स को गैर–कानूनी बनाने के लिए एक विधेयक लाई थी और इस विधेयक पर राज्यपाल की चुप्पी के कारण इन गेम्बलिंग ऐप्स को कानूनी शरण मिल गई। कई राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के खिलाफ इस विधेयक को मंजूरी न देने के खिलाफ विरोध किया था। यहां तक कि एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के तमिलनाडु में एक घटक पी.एम.के. के अध्यक्ष अनबुमनी रामदास ने इस मामले में राज्यपाल के कृत्य की भर्त्सना की थी।

तमिलनाडु के राज्यपाल ने हाल में कहा कि 'तमिलनाडु' के आधिकारिक नाम की जगह तमिषघम शब्द अधिक उचित है। पूरे राज्य ने राज्यपाल के इस वक्तव्य का विरोध किया। इसके तुरंत बाद राज्यपाल ने विधानसभा में अपने भाषण में कुछ शब्द हटा देने और कुछ और जोड़ देने से राज्य में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। विधानसभा के राज्यपाल के भाषण को उस राज्य की सरकार ड्राफ्ट करती है। राज्यपाल को इसे हू–ब–हू पढ़ना होता है। यदि उस ड्राफ्ट में कोई दिक्कत है तो राज्यपाल को पहले ही इसे सूचित और स्पष्ट करना होता है। तमिलनाडु के मामले में आर.एन. रवि और उनके कार्यालय ने राज्य सरकार को कहा कि उन्हें ड्राफ्ट मंजूर है।

राज्य सरकार को बिना सूचित किए राज्यपाल ने विधानसभा में बदला हुआ ड्राफ्ट (भाषण) पढ़ा और उसके बदले भाषण से वे सारे शब्द जैसे कि धर्मनिरपेक्ष, दविड़ीय मॉडल, सामाजिक न्याय, शांति जैसे शब्दों को हटा दिया। राज्यपाल ने भाषण से पेरियार, कामराज, अन्नादुरई, करूणानिधि सरीखे बड़े नामों को हटा दिया। यह अपने आपमें दिखाता है कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे के अनुसार किया गया था चूंकि आरएसएस को इन शब्दों और नामों से घृणा है।

यहां तक कि पुडुचेरी में जहां एन. आर. कांग्रेस नीत राजग सरकार है वहां के मुख्यमंत्री एन. रामगास्वामी ने राज्य सरकार के कामों में उपराज्यपाल के तमिलीसाई सौन्दरराजन के हस्तक्षेप के खिलाफ बोला। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि सरकार चलाना कठिन हो रहा है।

हमें समझना चाहिए कि भाजपा किस तरह से राज्यपाल के पद का दुरूपयोग कर रही है गैर–भाजपा शासित सरकारों के कामों में रूकावट डालने के लिए। राज्यों में राज्यपाल अधिनायकवादी बन रहे हैं। वे स्वयं को राज्यों की निर्वाचित सरकारों से अधिक शक्तिशाली सोच रहे हैं। यह जनतंत्र की मूलभावना के खिलाफ है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 29 दिसंबर 2022 को ''संघवाद बचाओ दिवस'' का आह्वान किया था और कई राज्यों में राज्यपालों के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। तमिलनाडु में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजभवन पर मार्च में 50,000 साथियों को गिरफ्तार किया गया। भाकपा महासचिव डी.राजा को भी भाकपा तमिलनाडु राज्य परिषद के नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया। ठीक इसी दिन दिल्ली में भी एक प्रदर्शन संगठित किया गया था। इस प्रदर्शन में भाकपा कार्यकारिणी सदस्य अमरजीत कौर ने भागीदारी की थी। देश भर में प्रदर्शन आयोजित किए गए थे।

भाकपा कांग्रेस ने राज्यपालों के पद को निरस्त करने हेतु संवैधानिक संशोधन लाने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था।

जैसे–जैसे राज्यपाल निरंकुशवादी बन रहे हैं और राजभवन कार्यालय निर्वाचित सरकारों के खिलाफ षड़यंत्र रचने की जगह बन रहे है। ऐसे में राज्यों में राज्यपाल के पदों को निरस्त करने की मांग तेज हो रही है। आओ, इस मुद्दे पर हम मिलकर काम करते हुए इसे जनआंदोलन बनाएं।

भाकपा का जन विरोधी बजट के खिलाफ प्रदर्शन
आंध्र पुनर्गठन कानून लागू करने की मांग

केंद्र सरकार ने एक बार फिर संयुक्त वारंगल जिले के बजट आवंटन में अड़ियल रूख दिखाया है।

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए जनविरोधी बजट को लेकर गुरुवार को वारंगल जिले में भाकपा द्वारा केंद्र सरकार का पुतला फूंक कर धरना प्रदर्शन किया गया।

केंद्रीय बजट से जिले के लोगों की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया है। जब से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है, वह तेलंगाना राज्य और संयुक्त वारंगल जिले के विकास के प्रति घोर उदासीन रही है। केंद्र ने राज्य के विभाजन के दौरान किए गए वादों को नजरअंदाज कर दिया था जैसे काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री, बय्याराम में स्टील उद्योग और मुलुगु में आदिवासी विश्वविद्यालय। बंटवारे के वादों के लिए आवंटन नहीं कर संयुक्त वारंगल जिले के साथ गलत किया गया है।

दूसरी ओर, मोदी सरकार अपनी पुरानी सोच को उजागर करना जारी रखे हुए है और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो मानती है कि वो सभी राज्यों को संतुलित तरीके से देखने वाली हैं, ने कर्नाटक को कर्ज दिया है, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 5,300 करोड़ रुपये की केंद्र सरकार की सहायता की घोषणा की। यह भाजपा शासित राज्यों और उन राज्यों के लिए सरकार का प्यार हैं जहां जल्द ही चुनाव होंगे।

वारंगल जिले में सिंचाई परियोजनाओं और कपड़ा उद्योग को नजरंदाज किया गया है।

मोदी सरकार जिसने हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, ने कोई रोजगार नहीं दिये, परंतु पिछले बजट में भी उसने रोजगार सृजन का वादा किया था जिसे भी वह भूल गयी है।

अडानी का गुब्बारा फूटा, निकला देश की लूट का सच

डॉ. सोमा मार्ला

फोर्ब्स ने दुनिया की वित्तीय समाचार दैनिक (सितंबर, 2022) में गौतम अडानी को वैश्विक अमीर सूची में दूसरे सबसे अमीर के रूप में दर्ज किया, फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपति रैंकिंग में अडानी की संपति 155.5 बिलियन डालर होने का अनुमान लगाया गया था। फिर इस सप्ताह के दौरान विश्वसनीय अमेरिकी वित्तीय जांच फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारत के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट अडानी साम्राज्य के स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी की एक गाथा का खुलासा किया। नतीजा यह हुआ कि 31 जनवरी की सुबह तक अडानी समूह को करीब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान हो चुका था। 5.2 लाख करोड़ (65 बिलियन डालर) और हिंडनबर्ग रिसर्च की लगभग 160 पेज लंबी रिपोर्ट जारी होने के बाद उनकी सबसे बड़ी कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य का लगभग 25 प्रतिशत तेजी से गिर गये।

दरियादिली से दिए गए कर्ज की लूट

पिछले नौ सालों में मोदी सरकार ने कई सार्वजनिक परिसंपत्तियों जैसे कि बंदरगाह, हवाई अड्डे, हाईवे, गैस, सीमेंट और सौर परियोजनाओं का न केवल निजीकरण किया बल्कि इसमें से कईयों को बिना किसी सशक्त प्रतियोगी के अडानी समूह को न्यौच्छवर कर दिया।

कोयला आयात और उपरोक्त सामाजिक परिसंपत्तियों को हासिल करने के लिए मौजूदा सरकार ने अडानी को भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी जैसे सार्वजनिक संस्थानों से बड़े पैमाने पर फंड भी उपलब्ध करवाएं। इन सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों ने बिना किसी सुरक्षा गारंटी के मात्र अडानी समूह की 'गुड विल' के नाम पर दसों और हजारों–करोड़ रुपये का कर्ज दे दिया। यह सब अडानी के मौजूदा भारतीय शासन के साथ घनिष्टतम संबंधों के कारण संभव हुआ। क्या वित्तीय संस्थानों से इसी तरह के व्यवहार की कल्पना कर सकते हैं कि जब एक स्वरोजगार लघु उद्यम या फिर किसान अपनी छोटी फसल के लिए कर्ज ढूंढता है।

अडानी समूह को विशाल परियोजनाओं के लिए वित्तीय देने के कारण भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी को हजारों–करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है और मीडिया खबरों में कहा जा रहा है कि इससे देश की पूरी वित्तीय व्यवस्था के खतरे में होने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2022 के मार्च महीने के अंत तक अनुमान लगाया गया है कि अडानी के दो लाख करोड़ रुपये के कर्ज़ का 40 प्रतिशत एलआईसी और भारतीय स्टेट बैंक वित्तीय संस्थानों समेत भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का है।

अडानी के बनावटी ढंग से बढ़ाए गए शेयरों पर अकेले एलआईसी ने 77,000 करोड़ का निवेश किया था जिसमें से एलआईसी के 23,500 करोड़ रुपये 4 दिनों के भीतर ही 30 जनवरी तक डूब गए।

सरकारी बैंकों ने अडानी को प्राइवेट बैंकों की तुलना में दोगुना कर्ज दिया। साफ है कि इससे करोड़ों भारतीयों की बैंकों में जमा मेहनत की गाढ़ी कमाई खतरे में है। इसके बावजूद अडानी समूह हिन्डनबर्ग के सिलसिलेवार आरोपों का पुख्ता जवाब नहीं दे सका और हिन्डनबर्ग के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण कहा और कहा कि हिन्डनबर्ग के आरोप भारत के विकास की सफलता को रोक रहे हैं। लगता है कि अडानी राष्ट्रवाद के नाम पर तिरंगा ओढ़कर गंभीर धोखेबाजी को छिपाने की कोशिश कर रहा है।

क्रोनी पूंजीवाद और भाजपा शासन के बीच मिलीभगत

अडानी उछाल जो कि सार्वजनिक संपत्ति और बैंकों के धन को डकारने के साथ वित्तीय सट्टाबाजारी और शेयर बाजार घोटाले पर टिकी है और यह पिछले दो दशकों में उसके सरकार के साथ घनिष्ठ संबंधों से संभव हुआ है। 2001 में अडानी एक छोटा उद्योगपति था अंबानी की तुलना में, और अंबानी की संपत्ति अडानी की तुलना में 500 गुना ज्यादा थी। तब से मोदी के आश्रय में अडानी की कायापलट भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट (निगम) और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धनवान के रूप में हुई है।

अडानी ने कॉलेज से ड्रॉपआउट होने पर 1980 में वस्तुओं के व्यापार कारोबार से अपने कैरियर की शुरूआत की थी। वह 1990 का उदारवाद–वैश्वीकरण की सरकार थी जिसने अडानी को 1995 में मुंद्रा बंदरगाह स्थापित करने लायक बनाया था। 2002 में अडानी की कंपनी की मुख्य संपत्ति का कुल मूल्य मात्र 700 लाख डॉलर था। लेकिन एक दशक के अंतराल में अडानी 2,00,000 लाख डॉलर की संपत्ति पर तेजी से पहुंच गया था, यह उसकी संपत्ति की 300 गुना बढ़त थी जो कि फोरब्स बिजनेस पत्रिका के अनुसार, कंपनियों के इतिहास में बिल्कुल अप्रत्याशित है।

मोदी के 8 सालों के कॉरपोरेट–भगवा शासन में अडानी की संपत्ति में 800 प्रतिशत की बढ़त हुई है। उदाहरण के लिए, 2019 में अडानी समूह ने सरकार द्वारा प्राइवेट किए गए सभी छह हवाई अड्डों की एक खेप को खरीद लिया, कानूनों में बदलावों के कारण एक ऐसी कंपनी जिसे हवाई अड्डों का कोई अनुभव नहीं था वह तेजी से भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा स्वामित्व वाला समूह बन गया। अडानी की बढ़त बैंकों से एक कारोबार पर लिए कर्ज को नए वित्तीय कारोबार में बढ़ाने से है।

अडानी ने गुजरात में मुंद्रा में एक बंदरगाह और स्पेशल इकोनोमिक जोन को विकसित किया। इस स्पेशल इकोनोमिक जोन को भारत में उसके सबसे बड़े कारोबारी साम्राज्यवाद के हब के रूप में बढ़ाना था जिसमें उसी जगह पर कोयले–से–प्लस्टिक फैक्टरी से लेकर ताँबा गलाने वाला संयंत्र शामिल था।

अडानी ने तेजी से जोरदार ढंग से स्वाभाविक रूप से पुनः पैदा होने वाली ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) जैसे कि अडानी ग्रीन्स के साथ स्वयं को सरकार के कार्बनरहित ऊर्जा के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ जोड़ लिया है, जबकि अडानी खुद एक भारत के कोयला–ज्वलित विद्युत संयंत्र का सबसे बड़ा ऑपरेटर है। अडानी एक फ्रांसीसी कंपनी 'टोटल एनर्जी' के साथ मिलकर ''ग्रीन हाइड्रोजन'' (हरित उदजनन) पर 200 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। पर 200 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है। हाल ही में अडानी ने एनडीटीवी के शेयरों का एक बड़े हिस्से को हासिल कर लिया–जो कि खुली पत्रकारिता के मुंह को बंद करने और बोलने की आजादी को दबाने की चाल है। यह क्रोनी पूंजीवाद को मजबूत करने का एक स्पष्ट कृत्य है।

वित्तीय पूंजी और सट्टाबाजारी

अडानी जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रोनी पूंजीवादी है। वह अपनी वित्तीय कंपनियों के साम्राज्य को मोदी सरकार की दक्षिणपंथी नव उदारवादी नीतियों जैसे कि कर छूट, मजदूर और पर्यावरण के कानूनों में ढील ने अडानी को बहुमूल्य राष्ट्रीय परिसंपत्तियों जिसमें कि जमीन, प्राकृतिक और खनिज संपदा, फैक्टरियों और उनके शेयरों को कौड़ी के भाव पर खरीदने में सक्षम बनाया है जबकि अडानी मुख्यतः सट्टाबाजारी में है। उसके कर्ज लिए गए धन का निवेश फर्जी कंपनियों, वित्तीय सट्टाबाजारी और शेयर बाजार में खरीद–फरोख्त पर है। यह निवेश एक तरह का गैर–उत्पादककारी निवेश है जो कि अडानी के लिए जल्दी से संपत्ति इकट्ठा करने का मंत्र है। वित्तीय–पूंजी चूंकि गैर–उत्पादककारी होती है वह मुख्यतः 'हाऊसिंग बब्बल' जैसे संकट और 2007 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के गिरने का कारक है। आज, अडानी की परिसंपत्तियां शेयर बाजार में 'जहर' बन रही है और इनके बड़े पैमाने पर शेयर बाजार में इनकी बिकवाली चल रही है। जिसके कारण भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी को भारी नुकसान पहुंच रहा है। भारत सरकार सरकारी खजाने से अडानी को ''बेलआउट' (बचाने) की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चूंकि भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी के नुकसान का बोझ आखिर में छोटे और मझोले खाताधारकों पर पड़ेगा। जनता को मजबूती के साथ क्रोनी पूंजीवाद को संकट से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा आगे किए जाने वाले किसी भी 'बेल आऊट' के प्रयास का विरोध करना चाहिए।

ट्रेड यूनियनें और जनता ने मौजूदा सरकार की उदारवादी नीतियों के खिलाफ, सार्वजनिक परिसंपत्तियों को बेचने के खिलाफ और क्रोनी पूंजीवाद के बेलआउट के खिलाफ संघर्ष शुरू किया हुआ है। इस संघर्ष को और ज्यादा मजबूत करने, जनता को उससे जोड़ने की जरूरत है ताकि आम जनता को और भारत की अर्थव्यवस्था को अडानी के वित्तीय गुब्बरे के फूटने से पहुंचने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

बजट 2023–24: एटक

मोदी सरकार द्वारा पेश बजट जनविरोधी: भाकपा

पटना: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिवमंडल ने संसद में पेश केंद्रीय बजट 2023–24 पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोदी सरकार बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती असमानता, मुद्रास्फीति और उभरते बहुआयामी ग्रामीण संकट पर ध्यान देने में विफल रही है।

बजट में अर्थव्यवस्था की जमीनी हकीकत की उपेक्षा की गई है। यह बजट गरीब, मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और महिला विरोधी है। भाकपा राज्य सचिव राम नरेश पाण्डेय ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली मोदी सरकार द्वारा पेश बजट को जनविरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, खाद्य सुरक्षा और अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लिए आवंटित की गई राशि अपर्याप्त है। यह मेहनतकश जनता के लिए एक बड़ा झटका है। इस बजट से महंगाई और बढ़ेगी और आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

कृषि पर आवंटन 8500 सौ करोड़ रुपये से कम कर दिया गया है जबकि किसान खेती में उच्च लागत से परेशान हैं। बजट में किसानों के मदद के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। किसानों को खाद पर सब्सिडी कम कर दी गई है। खाद पर मिलने वाले 2.8 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी को घटाकर 1.97 लाख करोड़ कर दिया गया है। आईसीडीएस के आवंटन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मनरेगा में आवंटन काफी कम कर दिया गया है। मनरेगा मद में वर्ष 2022–2023 के लिए 89,000 करोड़ रुपये का आवंटन था, जिसे घटाकर इस बजट में 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मनरेगा के बजट में कटौती से ग्रामीण रोजगार पर असर पड़ेगा। मोदी सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दो गुनी करने की घोषणा की थी, लेकिन किसानों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए हैं। लोक कल्याणकारी योजनाओं में राशि की कटौती कर ली गई है। यह बजट पूरी तरह पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि बजट जनविरोधी, विकास विरोधी, महिला, गरीब, किसान, नौजवान, छात्र मजदूर विरोधी और कारपोरेट घरानों के हितैषी है।

प्रदेश भर में धरने, प्रदर्शनों के साथ भाकपा का अभियान ...

पेज 7 से जारी...

आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में गरीबी रेखा के नीचे उत्तर प्रदेश में 37.79 फीसद लोग है। घनघोर संकटमय स्थिति है।

महंगाईः महगाई निरन्तर बढ़ रही है। एक तरफ देश के धनपति दुनिया के सबसे अमीर लोग हो गए हैं तो दूसरी तरफ 45 फीसदी से अधिक जनता गरीबी की रेखा के नीचे पहुंच गई है और प्रतिदिन का सामान जुटाना या दो वक्त की रोटी नसीब होनें मैं लाले पड़े हुए हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 11 तारीख से 17 तारीख तक जन जागरण किया है और इन प्रश्नों को जनता के बीच में ले गए हैं। विचार गोष्ठियों के द्वारा, छोटी–छोटी नुक्कड़ सभाओं के द्वारा, साइकिल जलूसों द्वारा एवं पर्चा वितरण करके।

18 तारीख को पूरे प्रदेश में एक साथ धरना/प्रदर्शन करके अपनी मांगों को आपके समक्ष रख रहे हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सोच है कि जब तक इन नीतियों को चलाने वाली सरकार को बदला नहीं जाएगा तब तक उत्तर प्रदेश की जनता के सामने संकट बना ही रहेगा और उसको निरंतर रोजी–रोटी के लाले पड़े रहेंगे और उसके विरुद्ध कुछ ना कुछ होता रहेगा।

कहा गया कि ज्ञापन के द्वारा इन समस्याओं को आपके समक्ष रखते हुए आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि आप अपनी सरकार को निर्देश दें कि वह इन नीतियों को शीघ्रता शीघ्र बदलें। जब तक यह नीतियां बदली नहीं जाएंगी जनता तो संघर्ष करती ही रहेगी और किसान मजदूरों की पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने लक्ष्य के लिए निरंतर संघर्ष जारी रखेगी।

समाचार लिखे जाने तक कार्यक्रम और ज्ञापन दिए जाने की, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, भदोही, झांसी, जालौन, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, कानपुर नगर, अलीगढ़, मथुरा सुल्तानपुर, हाथरस, महाराजगंज, बरेली, बदायूँ, औरैया, मुजफरनगर, बान्दा,चित्रकूट, आजमगढ़, अयोध्या, फतेहपुर, गोंडा, सोनभद्र से सूचना प्राप्त हो चुकी है।

विभिन्न जिलों में चला सघन अभियान

भदोही

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रव्यापी आवाहन पर 'आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ, भाजपा हटाओ' के नारे के तहत भाकपा जिला कमेटी भदोही ने लगातार तीसरे दिन 13 जनवरी को गामसभा बेजवां बिकास खण्ड औराई में कई गांवों में जन जागरण अभियान चलाकर ओ एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया! सभा को मुख्य रूप से भाकपा राज्य सचिवमण्डल सदस्य फूलचन्द यादव, जिला मंत्री राजेन्द्र प्रसाद कनौजिया, जिला सचिवमण्डल सदस्य लल्लन मौर्या ने सम्बोधित किया।

आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ, इन्हीं प्रमुख मुद्दों को लगातार चौथे दिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी भदोही ने 14 जनवरी को गामसभा मंत्री राजेन्द्र प्रसाद कनौजिया, उर्मिला देवी, अशोक चौहान आदि साथियों ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता अमरावती देवी ने की।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी भदोही ने 16 जनवरी को लगातार पाचवें दिन आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ नारे के तहत गामसभा भुलाईपुर में कई गावों में जन जागरण करने के बाद एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। सभा को भाकपा राज्य सचिवमण्डल सदस्य फूलचन्द यादव

कसिदहां ; ज्ञानपुर में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया! भाकपा राज्य सचिवमण्डल सदस्य फूलचन्द यादव ने सभा में चारों बिन्दूओं पर विधिवत प्रकाश डालते हुए 18 जनवरी को जिला मुख्यालय पर किये जाने वाले प्रदर्शन में आमजन से समर्थन मांगा, उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर, करतल ध्वनि के साथ तालियां बजाकर कार्यकम में भागीदारी करने का आश्वासन दिया। सभा को जिला मंत्री राजेन्द्र प्रसाद कनौजिया, सहायक मंत्री कान्तिभूषण मौर्या, जिला सचिवमण्डल सदस्य रामसजीवन, दिनेश चन्द्र यादव, सुरेन्द्र भारती एडवोकेट, भाकपा राज्य कौंसिल सदस्य भूलाल पाल आदि साथियों ने सम्बोधित किया। सभा की अध्यक्षता ग्राम प्रधान कोमल भारती एडवोकेट ने की!

15 जनवरी को आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ नारे के तहत गामसभा बदली पुर, सुरियावां में लगातार पांचवे दिन गांव बटोर नुक्कड़ सभा का आयोजन जिला कमेटी भदोही ने किया! भाकपा राज्य सचिवमण्डल सदस्य फूलचन्द यादव ने चारों बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए 18 जनवरी को जिला मुख्यालय पर किये जाने वाले पढदर्शन में बड़ी संख्या में शिरकत करने का आह्वान किया। सभा को भाकपा राज्य कौंसिल सदस्य भूलाल पाल, जिला ने चारों मुद्दों पर बिधिवत प्रकाश डालते हुए सभा में उपस्थित लोगों से 18 जनवरी को जिला मुख्यालय पर किये जाने वाले प्रदर्शन में बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लेकर प्रदर्शन को सफल बनाने की गुजारिश किया। उपस्थित लोगों ने कार्यक्रम को भरपूर समर्थन देते हुए प्रदर्शन में शिरकत करने का आश्वासन दिया। सभा में भाकपा राज्य कौंसिल सदस्य भूलाल पाल, जिला मंत्री राजेन्द्र प्रसाद कनौजिया, सह मंत्री चन्द्रमा बनवासी, सिद्धनाथ राजभर, रामलाल बनवासी, रामनारायण यादव, मौजूदा ग्राम प्रधान कल्लू राम यादव आदि साथियों ने अपने विचार ब्यक्त किये। सभा की अध्यक्षता पूर्व गाम प्रधान रामबली यादव ने किया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला कमेटी ने 17 जनवरी को आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ, संविधान बचाओ, भाजपा हटाओ मुद्दे को लेकर लगातार सातवें दिन कांवल बारीपुर में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। सभा को भाकपा राज्य सचिव मण्डल सदस्य फूलचन्द यादव, राज्य कौंसिल सदस्य भूलाल पाल, जिला मंत्री राजेन्द्र प्रसाद कनौजिया ने सम्बोधित किया और 18 जनवरी 2023 को जिला मुख्यालय पर किये जाने वाले प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील किया।

गाजीपुर

18 जनवरी आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ, महंगाई हटाओ, भाजपा सरकार हटाओ प्रांतीय अभियान के अंतिम दिन जिला मुख्यालय स्थित सरजू पाण्डेय पार्क में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गाजीपुर ने धरना दिया। इसे सम्बोधित करते हुए पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य अमेरिका सिंह यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार संविधान की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को समाप्त करने पर तुली हुई है। संविधान में सामाजिक आर्थिक, रूप से विकास में पीछे रह गये लोगो को आगे बढ़ाने हेतु आरक्षण करने, आर्थिक असमानता कम करने का प्रावधान है। परन्तु यह सरकार अपनी अघोषित नीतियों के तहत उक्त प्रावधानों को खत्म करना चाहती है। इसका सबूत स्थानीय निकाय चुनाव में जानकारी होने के बावजूद भी मनमाने ढंग से सीटें आरक्षित की गई। फलस्वरूप उच्च न्यायालय ने आरक्षण ही खत्म कर दिया। इसी प्रकार सर्वजनिक प्रतिष्ठानो का निजीकरण करके रोजगार के अवसर को भी समाप्त करते जा रहें है। युवाओं का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। महंगाई ने लोगों की कमरतोड़ दिया है। जो सरकार जानता की समस्याओं को हल न कर सके उसको सत्ता में रहने का हक नहीं है। किसान सभा के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि सरकार में बने रहने के लिए भाजपा सरकार जातीय और विभाजनकारी नीतियों का अनुसरण कर रही है। किसान मजदूर तबाह और बर्बाद हो रहा है। जिला सचिव जनार्दन राम ने जनविरोधी नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि संविधान, आरक्षण, राष्ट्र बचाने हेतु भाजपा सरकार को हटाना होगा। इसके लिये लगातार संघर्ष चलाना होगा। धरना को सहसचिव ईश्वरलाल, रामावध, डॉक्टर रामबदन सिंह, फूल मैन, श्यामा प्रसाद, ओमप्रकाश गुप्ता, बटोर गुप्ता, रामजन्म, रामकेर यादव, राम शुक्ला अंगद यादव, चतुरी बिंद, मनीराम, आदि ने सम्बोधित किया। अंत में महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। अध्यक्षता अमेरिका सिंह यादव एवं संचालन रामावध ने किया।

फतेहपुर

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला काउंसिल काउंसिल के द्वारा प्रांतीय आवाहन पर संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, महंगाई घटाओ, भाजपा हटाओ, नारे के तहत खागा तहसील में जोरदार धरना प्रदर्शन करते हुए 3 सूत्री ज्ञापन एसडीएम खागा के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा गया जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण और सरकार की तमाम जन विरोधी गतिविधियों को उजागर किया गया। धरने में उपस्थित जिला काउंसिल के नेताओं ने अपने विचार रखते हुए सरकार की तमाम नीतियों का विरोध किया। धरने को संबोधित करने वालों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव फूल चंद पाल, राज्य सचिवमंडल के साथी मोतीलाल एडवोकेट, सह सचिव रामप्रकाश, राज्य काउंसिल के सदस्य रामचंद्र, पूरनलाल, छोटेलाल, इमरोज, मनोज, रामरूप सहित जंग बहादुर सिंह, सुमन सिंह चौहान, राम अवतार सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

चित्रकूट

18 जनवरी भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रादेशिक आवाहन पर चित्रकूट इकाई ने अमित यादव एड. के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का हुजूम कार्यालय से नारेबाजी आरक्षण खत्म करने की साजिश बंद करो, बेरोजगारों को रोजगार दो, महंगाई कम करो, इंकलाब जिंदाबाद के बुलंद नारों के साथ तहसील मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन कर सभा में तब्दील हो गया। सभा की अध्यक्षता कमलेश प्रसाद ने की। अमित यादव ने कहा कि 11–17 जनवरी तक 'आरक्षण बचाओ, रोजगार बचाओ और भाजपा हटाओ' अभियान भाकपा के प्रादेशिक आह्वान पर पूरे जिले में पार्टी परचे बांटकर, नुक्कड़ सभा व चौपाल के माध्यम से सरकार की जनविरोधी नीतियों को जनता के समक्ष रखकर जनजागरण अभियान चलाया जा रहा है तथा जिले के सभी वरिष्ठ नेता कमर कसकर इस अभियान के तहत जनता के बीच पहुंच रहे हैं। भारत का संविधान जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर किसी भी वर्ग में भेद नहीं करता लेकिन आजकल इन्हीं शब्दों के आधार पर बीजेपी आरएसएस की सत्ताधारी

शेष पेज 15 पर...

संदर्भ: 4 फरवरी, मजदूरों के रहनुमा शायर मखदूम मुहिउद्दीन के जन्मदिवस पर विशेष

हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो

जाहिद खान

साल 1936 में लखनऊ में अजीम उपन्यासकार प्रेमचंद की सदारत में एक बड़े जलसे के साथ 'प्रगतिशील लेखक संघ' की स्थापना हुई। उसके बाद पूरे मुल्क में इसकी इकाईयों का विस्तार हुआ। बंबई में भी 'अंजुमन तरक्कीपसंद मुसन्निफीन' की मुकामी शाखा के हर हफ्ते जलसे हुआ करते थे। मुकामी शाख के सेकेट्री हमीद अख्तर इन इजलास (सभा) की रूदाद (वृत्तांत) लिखते थे। जो उस वक्त बंबई से शाया (प्रकाशित) होने वाले हफ्तावार 'निजाम' में शाए होकर बर्र ए सगीर (उप महाद्वीप) के कोने–कोने तक पहुंचती थी। मुल्क के तमाम बड़े–बड़े अदबी मराकिज (केन्द्रों) में इसका बेचैनी से इंतजार किया जाता था। ये तरक्कीपसंद तहरीक के उरूज का जमाना था। और इस तहरीक से मुताल्लिक तकरीबन सभी बड़े नाम सज्जाद जहीर, अली सरदार जाफरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कृश्न चंदर, सआदत हसन मंटो, ख्वाजा अहमद अब्बास, अख्तर उल ईमान, विश्वामित्र आदिल, इस्मत चुगताई, सुल्ताना बेगम, मजाज, कैफी आजमी, कुद्दूस सहबाई, मीराजी, साहिर लुधियानवी, जांनिसार अख्तर, राजिंदर सिंह बेदी, प्रेम धवन, मोहम्मद मेहदी, मधुसूदन, सागर निजामी और जोय अंसारी इसके अलावा और भी कई बड़े नाम उस वक्त बंबई में मौजूद थे। जिनकी अक्सरियत (बहुतायत) इन हफ्तावार अदबी जलसों में शरीक होती।

1946–47 का जमाना तरक्कीपसंद तहरीक के लिए इस लिहाज से भी अहम था कि इस जमाने में मुल्क में आजादी की लहर जारी और सारी थी। और तरक्कीपसंद मुसन्निफीन की तंजीम आजादी की इस जद्दोजहद का एक इंतिहाई सरगर्म हिस्सा थी। चूंकि उस जमाने में तकरीबन सभी नामवर तरक्कीपसंद अदीब और शौहरा बंबई या पूना में मौजूद थे। और बाकायदगी के साथ अंजुमन के हफ्तावार जलसों से शरीक भी होते थे। इसलिए इन जलसों की रूदाद और उसके रिकार्ड को यकीनन तारीखी हैसियत का हामिल करार दिया जा सकता है। इन जलसों में उठाए जाने वाले सवालात जिनका तअल्लुक उस दौर की सियासी, तहजीबी, सकाफती (सांस्कृतिक) और अदबी जिंदगी से था। उनमें होने वाली बहसों से यह अंदाजा किया जा सकता है कि उन लोगों की सोच क्या थी।

1946–47 के डेढ़ बरसों में 'अंजुमन तरक्कीपसंद मुसन्निफीन' की मुंबई शाख के हफ्तावार जलसों की यह रूदाद किताब 'रूदाद ए अंजुमन' में मौजूद है। जिसे साल 2006 में 'तख्लीककार पब्लिशर' दिल्ली ने उर्दू में शाया किया था। 75 साल पहले 22 दिसम्बर, 1947 के दिन 'अंजुमन तरक्कीपसंद मुसन्निफीन' के जलसे में क्या हुआ था? पेश है उसकी पूरी रूदाद, जो इस अहमतरीन किताब में दर्ज है। इस इजलास में सज्जाद जहीर ने अपनी तकरीर में मखदूम मुहिउद्दीन के बारे में जो कहा और अली सरदार जाफरी ने अपने एक आलेख में उनकी एक नज्म 'ये जंग है जंगे आजादी' का जो शानदार तब्सिरा किया, वह वाकई काबिले गौर है।

22 दिसम्बर, 1946

उर्दू तरक्कीपसंद मुसन्निफीन का ये जलसा 22 दिसम्बर को यौम ए मखदूम की शक्ल में मुनअकिद हुआ। हाजिरीन (उपस्थित जनसमूह) की

तादाद आज के जलसे में निस्बतन ज्यादा थी। तरक्कीपसंद मुसन्निफीन की गुजिश्ता मीटिंग में दीवारी अखबार की तजवीज पेश की गई थी। इस हफ्ता इस तजवीज पर अमल शुरू हुआ था। इस हफ्ते के दीवारी अखबार के दरमियान में मोटे कलम से मखदूम का ये शे'र लिखाई देता था,

हयात ले के चलो, काएनात ले के चलो

चलो तो सारे जमाने को साथ ले के चलो।

और इस शे'र के ऐन ऊपर मखदूम की एक बड़ी सी तस्वीर आवेजाँ (लटकाया हुआ) थी। सियाही माइल (हलका कालापन लिए हुए) चेहरे पर वही जानी–पहचानी मुस्कराहट खेल रही थी। एक नजर देखने पर मालूम होता था,जैसे खुद मखदूम बैठा पूरे यकीन से कह रहा हो। ''मैं जानता हूं तुम इस राज को समझ रहे हो और मैंने समझ लिया।

हयात ले के चलो, कायनात ले के चलो

चलो तो सारे जमाने को साथ ले के चलो।

इसलिए मैं अवामी ताकतों की मशाल लिए हर भटकने वाले को राह दिखा रहा हूं और दक्खन की स्याह पथरीली धरती पर खुश्क चट्टानों के पीछे एक नई फौज तैयार कर रहा हूं। जिसने हर अत्याचारी ताकतों के सामने सीना तानकर लड़ने का फैसला कर लिया है। जो मुस्तकबिल के मैमारों (निर्माताओं) की फौज है। और जो सारे जमाने को साथ लेकर चलने के लिए उठी है। उनके जिस्म सदियों के जुल्म से दब गए हैं। मगर अब अपने पुराने लिबास को उतार रहे हैं। ये बहुत भोले हैं, मासूम हैं, सादा हैं। अपनी राह में बिछे हुए कांटों को हटाने से डरते हैं। मैं पूरी कुव्वत से आगे बढ़कर इनसे निजात पाने के लिए कह रहा हूं। क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैं तुम्हारी आवाज का मुंतजिर (प्रतिक्षा में होना) हूं।''

मीटिंग शुरू होते है सेक्रेटरी ने पिछले हफ्ते की रूदाद पढ़कर सुनाई। इसके बाद सज्जाद जहीर ने यौम ए मखदूम के मुताल्लिक अपने ख्यालात का इजहार करते हुए, ''मखदूम की शायरी और शख्सियत का मुख्तसर तआरूफ कराया। उन्होंने कहा, ''आज हर तरफ से रज'अत–परस्त (रूढ़ीवादी), तरक्कीपसंदों पर हमला कर रहे हैं और हमले उस वक्त तक खत्म नहीं होते, जब तक उस रज'अत परस्ती का खात्मा नहीं हो जाता। और यह ऐसी सूरत में मुमकिन है जब हम शे'र–ओ–अदब में तरक्कीपसंदी के साथ–साथ अमली दुनिया में पूरे तरक्कीपसंद हो जाएं। ऐसे तरक्कीपसंद जैसा कि मखदूम है।'' उन्होंने बतलाया, ''मखदूम हैदराबाद के कॉलेज में प्रोफेसर थे। नजरियाती तौर पर वो बहुत पहले तरक्कीपसंद हो गए थे। ये उन दिनों का जिक्र है, जब हमारे साथी सिब्ते हसन भी हैदराबाद में थे। सिब्ते हसन और मखदूम में बहुत मुबाहिसे (वाद विवाद) होते रहते थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि मखदूम न सिर्फ मुकम्मल तरक्कीपसंद शायर हो गए, बल्कि वो पूरे तरक्कीपसंद इंसान भी बन गए। और इस तरह उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया, जब उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अभी और बढ़ाया जाए। चुनांचे वो नौकरी छोड़कर अपना वक्त मजदूरों और किसानों को देने लगे। अदबी मश्आश (जमीन) पर उन्होंने हैदराबाद को रियासत होने के बावजूद तरक्कीपसंद अदब का एक मजबूत किला बना दिया। और आज हैदराबाद में जब भी कोई कॉफ्रेंस या मुशायरा किया जाता है, इसका मतलब तरक्कीपसंदों का इज्तिमा होता है। सियासी मश्आश पर मखदूम पच्चीस हजार मजदूरों को ट्रेड यूनियनों में लाए। आज वो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदर और वहां के मजदूर और किसानों के महबूब रहनुमा हैं।''

सिलसिला ये कलाम जारी रखते हुए उन्होंने कहा, ''इन दिनों हैदराबाद की हुकूमत हर तरह से अवामी तहरीकों को दबाने की कोशिश कर रही है। वहां कम्युनिस्ट पार्टी को और मजदूरों के इदारों को गैर–कानूनी करार दिया गया है। मखदूम के वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन वो मजदूर रहनुमा:–पोश (गुप्त) होकर बराबर टकरा रहे हैं।'' आखिर में उन्होंने कहा, ''हमने फैसला किया है कि हम मखदूम और हैदराबाद की मौजूदा अवामी तहरीक से मुताल्लिक एक पेम्पलेट शाए करें, ताकि अंजुमन के एक मुमताज मेंबर की जिंदगी को मिसाल के तौर पर पेश किया जा सके।''

'यौम ए मखदूम' के सिलसिले में मरकजी अवामी तहजीबी दस्ते के तीन रुक्न (मेम्बर) बना दिए। प्रीति, सरकार और प्रेम धवन भी आज की महफिल में शरीक हुए थे। सज्जाद जहीर की इस मुख्तसर तकरीर के बाद इन तीनों ने मखदूम का मशहूर तराना 'ये जंग है, जंग–ए–आजादी' गाया। इसके बाद सरदार जाफरी ने 'सुर्ख सबेरा का शायर' के उन्वान से अपना मजमून (आलेख) पढ़ा। मजमून काफी तवील और बेहद दिलचस्प था। मखदूम की शख्सियत और शायरी पर इतना अच्छा तब्सिरा गालिबन पहले कभी नहीं हुआ। बनारस जेल में सरदार जाफरी और मखदूम की पहली मुलाकात से लेकर आज तक के मखदूम पर ये मजमून बेहद पसंद किया गया। सद्रे जलसा इस मजमून से काफी मुतास्सिर हुए और उसके बाद खात्में पर उन्होंने कहा कि ''इस मजमून पर तो गालिबन कुछ नहीं कहा जाएगा।'' लेकिन जोय अंसारी साहब ने अपने आईनी (नियम और कानून) लहजा में सद्र को तंबीह (आगाही) करते हुए फौरन जवाब दिया, ''ये फैसला आपने कैसे किया?'' सद्र साहब झेंप गए। और जोय अंसारी साहब के वुजूद पर ईमान लाते हुए बोले, ''फरमाईए।'' जोए अंसारी ने मख्सूस (विशिष्ट) लहजे में जवाब दिया, ''जाफरी साहब नस्र की गालिबन ये पहली चीज है, जो मैंने आपसे सुनी है। और इसे सुनने के बाद मेरा ये यकीन मुतजलजल (कंपायमान) हो गया है कि आप सिर्फ नज्म ही अच्छी लिखते हैं, लेकिन एक बात कहूं कि इकबाल और टैगोर के कौमी और मखदूम के बैनल–अकवामी (अन्तर्राष्ट्रीय) तरानों के मुकाबले का टकराव, कुछ गैर मौजूँ सा मालूम होता है।''

सरदार जाफरी ने कहा कि, ''उन्होंने यही लिखा है कि इकबाल का 'सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा' और टैगोर का 'जन गण मन अधिनायक' दोनों जुगराफियाई (भूगोलिक) वहदत (गुण या भाव) लिए हुए हैं। लेकिन मखदूम की नज्म की सरहदें कहीं खत्म नहीं होतीं।'' इसकी वजाहत (विस्तार) करते हुए उन्होंने कहा, ''चूंकि इकबाल ने ये नज्म 1905 में लिखी थी। जब हमारी तहरीक इतनी उठी हुई नहीं थी, जितनी कि अब है। जब मखदूम ने ये नज्म लिखी और टैगोर ने भी हिंदोस्तां के ही हुस्न, अज्मत और बुजुर्गी को बयान किया है। जो जुगराफियाई

शेष पेज 15 पर...

सरला शर्मा: असाधारण कम्युनिस्ट...

पेज 5 से जारी...

की और चित्तप्रसाद की चित्रकारी भी शामिल थी। सुनील जाना के फोटो भी प्रदर्शित किए गए।

साप्रदायिक दंगों के दौरान सरला ने चांदनी चौक में पीड़ितों के बीच सक्रिय काम किया। उन्होंने बच्चों में दूध इ. बांटने का काम किया। उन्होंने गली–गली घूमकर लोगों के बीच राहत का काम किया। वे सभी उन्हें लंबे समय तक याद करते रहे।

इस सबके अलावा सरला दिल्ली की जनता के बीच उनकी सामाजिक, नागरिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य–संबंधी, सांस्कृतिक, शोषण–सबंधी इ. समस्याओं के हल के लिए भी सक्रिय रहीं। उनका नाम बेगम हाशमी, सत्यवती, चांदो बीबी, मेमोबाई, अरूणा आसफ अली, इ. के साथ लिया जाने लगा।

आजादी के बाद

1948–50 के दौरान भा.क.पा. पर अति–दुस्साहसवादी संकीर्ण 'बी.टी. आर. लाइन' हावी हो गई। इससे दिल्ली तथा समूचे भारत में पार्टी लगभग बर्बाद हो गई।

पार्टी के नेता अंडरग्राउंड चले गए। सरला 8 अक्टूबर 1948 से 17 नवंबर 1948 तक गिरफ्तार होकर जेल में रहीं। जेल में उन्होंने भूख–हड़ताल भी की। रिहाई के बाद वे अचानक गायब हो गईं और लगभग दो वर्षों तक लुप्त रहीं।

1950 के दशक के आरंभ में सरला ने दिल्ली में पार्टी को फिर से संगठित करने में सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने महिला संगठन फिर से खड़ा किया। अब इसका नाम जनवादी महिला समाज कर दिया गया। इसकी 22 शाखाएं थी। सरला 1953 में इसकी सचिव बनाई गई।

सरला शर्मा भारतीय महिला फेडरेशन (एन.एफ.आई.डब्ल्यू.) की संस्थापक नेताओं में थीं। इसका स्थापना सम्मेलन 1954 में दिल्ली में किया गया। वे 1962 से 1970 तक इसके सचिवों में थीं। 1970 में लेनिन की जन्मशती के अवसर पर उन्हें 'लेनिन मेडल' से सम्मानित किया गया।

विवाह

सरला गुप्ता का विवाह 1953 में वाई.डी. शर्मा के साथ हुआ। 'वाई.डी.' ए. आई.एस.एफ. और दिल्ली पार्टी के सक्रिय नेता थे। सरला गुप्ता अब सरला शर्मा बन गई।

चुनावों में

सरला शर्मा 1954 के दिल्ली म्युनिसिपल चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी की उम्मीदवार के रूप में खड़ी की गई। उनका चुनाव अभियान बड़ा ही प्रभावशाली रहा और वे चुन ली गई। म्युनिसिपल कमिटि के सदस्य के रूप में उन्होंने स्कूलों, पानी, मुस्लिम महिलाओं, इ. के लिए बड़ा ही योगदान दिया। जब 1958 में दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन का गठन हुआ तो वे फिर से चुन ली गई और बड़ा सक्रिय काम किया। वे कारपोरेशन की शिक्षा समिति की उपाध्यक्ष भी चुन ली गई।

आंदोलन

11 सितंबर 1973 को सरला शर्मा के नेतृत्व में एक डेप्यूटेशन पुराने सचिवालय भवन गया। वहां उसने नागरिक आपूर्ति के कार्यकारी काउंसलर को घेर लिया और अपनी मांगे पेश कीं। साथ ही मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों से भरे खराब राशन के पैकेट भी पेश किए। एक अन्य डेप्यूटेशन 19 मार्च 1974 को मिला। 1984 के सिख–विरोधी दंगों के दौरान सरला तथा अन्य ने शांति मार्च निकाले।

सम्मेलनों में

सरला शर्मा ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हिस्सा लिया। मसलन, उन्होंने बर्लिन में आयोजित विश्व महिला फेडरेशन की सातवीं कांग्रेस में हिस्सा लिया। वही, 1975 का, वर्ष विश्व महिला वर्ष भी था। इसे अटूबर 1975 में मनाया गया।

सरला शर्मा दिल्ली महिला संघ की महासचिव और फिर 1984 में अध्यक्ष बनीं।

उन्होंने कई लेख और पुस्तकें लिखीं। उन्होंने बहाल सिंह की जीवनी हिंदी में 1975 में लिखी।

सरला शर्मा का देहांत 11 अप्रैल 2022 को हुआ। चार ही दिनों बाद वे 102 वर्ष की हो जातीं। उनकी मृत्यु लंबी बीमारी के बाद हुई।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिका: भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़: प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाष: 011–23523349, 23529823
ईमेल: pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोन: 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोन: 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोट: आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरण:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट: 32074674284, आई.एफ.सी. कोड: SBIN0009371

हयात ले के चलो, कायनात ले के ...

पेज 13 से जारी...

वहदत लिए हुए है। लेकिन मखदूम कहता है,

सारा संसार हमारा है
पूरब पच्छिम उत्तर दक्कन
हम अफरंगी, हम अमरीकी
हम चीनी, जांबाजाने वतन
हम सुर्ख सिपाही, जुल्म शिकन
आहनपैकर फौलादबदन।

क्यों कि इस वक्त मुल्कों की सरहदें खत्म हो चुकी हैं।'' उन्होंने कहा कि ''मजमून के इसी टुकड़े के साथ एक फिकरे (एक वाक्य का एक हिस्सा) में इकबाल और टैगोर की शख्सियात को हिमालय और मखदूम को दरिया से तुलना दी गई है।'' सज्जाद जहीर, ''आपने अपने मजमून में टैगोर और इकबाल की शख्सियात से मखदूम की शख्सियत का मुकाबला किया है। या इन दोनों की नज्मों से मखदूम की नज्म का।'' सरदार जाफरी, ''सिर्फ इन तीनों नज्मों का जिक्र किया है और इसकी वजह ये बताई जा चुकी है कि ये मजमून लिखने का ख्याल मुझे एक ऐसी महफिल में सूझा था, जहां मुख्तलिफ सूबों के आदमी जमा थे। और जहां ये तीनों नज्में पढ़ी गई थीं। जहां तक शख्सियात के मुकाबले का तअल्लुक है, वो तो हो ही नहीं सकता। और न ही इसका सवाल पैदा होता है।''

जोय अंसारी ने सरदार जाफरी से एक और सवाल पूछते हुए कहा, ''जहां आपने दरमियानी तबके की कद्रों (मूल्यों) को रौंद कर आगे बढ़ने का जिक्र किया है, वो कुछ समझ में नहीं आया?'' सरदार जाफरी ने कहा कि, ''एक दौर में दरमियानी तबके की हर कद्र को रौंदना ही तरक्कीपसंदी समझा जाता था।'' इस सिलसिले में उन्होंने बतलाया कि, ''अक्सर औकात (समय का बहुवचन) किसी अमीर दोस्त के सोफे पर बैठकर बीड़ी पीने को तरक्कीपसंदी समझा जाता रहा है। हालांकि ये दुरुस्त नहीं।'' मधूसूदन ने सरदार जाफरी से पूछा कि ''इस मजमून में आपने एक जगह लिखा है कि आज का शायर मजदूरों में काम करके ही लिख सकता है। और ये कि ये बात मखदूम अपने तजुर्बे की बिना (आधार) पर कहता है कि मजदूरों में जाकर इंसान अपनी जड़ें धरती की गहराई में महसूस करता है। लेकिन एक दूसरी जगह आपने लिखा है कि मखदूम ने कहा कि मजदूरों में काम करने के बाद शायरी जारी नहीं रखी जा सकती।'' सरदार जाफरी, ''इससे मुराद ये है कि मजदूरों में बारह–चौदह घंटे काम करने के बाद इतनी फुर्सत नहीं होती कि इंसान बाकायदा शे'र लिखता रहे। ये बात अगर फिकरे से साफ तौर पर वाजेह (स्पष्ट) नहीं होती, तो उसे वाजेह तौर पर लिख दिया जाएगा।'' इसके बाद मजरूह सुल्तानपुरी ने मखदूम की मशहूर नज्म 'इंकलाब' सुनाई। जिसका टीप का मिसरा ये है

गुजर भी जा के तेरा इंतजार कब से है।

जोय अंसारी ने 'मखदूम' के उन्वान से एक नज्म सुनाई। जो बेहद पसंद की गई। मजरूह सुल्तानपुरी ने कहा कि ''इस नज्म में दर्द को मुअन्नस (स्त्रीलिंग) बांधा गया है। हालांकि 'दर्द' मुजक्कर (पुल्लिग) है।'' जोय अंसारी, ''दर्द' फारसी का लफ्ज है, और इसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है।'' विश्वामित्र आदिल, ''तो पिदर (बाप) और मुर्ग को आप क्या कहेंगे?'' जोय अंसारी, ''इसका फैसला ये लफ्ज इस्तेमाल करने के तसव्वुर के एहसास से हो सकता है।'' बाकायदा प्रोग्राम खत्म होने के बाद प्रीति ने प्रेम धवन का लिखा हुआ एक गाना सुनाया, जो तहजीबी दस्ते (सांस्कृतिक मोर्चे) ने फसाद (साम्प्रदायिक झगड़ा) के मौजू के लिए तैयार किया था। और बीना राय ने एक बंगाली गीत सुनाया। इसके बाद प्रेम धवन ने दो गीत सुनाए। एक पंजाबी और एक हिंदुस्तानी। और ये मजलिस (सभा) खत्म हुई।

(लिप्यंतरण जाहिद खान और इशरत ग्वालियरी)

प्रदेश भर में धरने, प्रदर्शनों के साथ भाकपा...

पेज 11 से जारी...

सरकार आदमी, आदमी और महिला, महिला के बीच खाई बढ़ाने की पुरजोर कोशिश में दिन रात जुटी है। उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की आरक्षण विरोधी नीति स्पष्ट हो गई है। जब सुप्रीम कोर्ट का 2021 का फैसला था तो उसके आधार पर ओबीसी जातियों का सर्वे क्यों नहीं करवाया गया जो अपने आप में बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतागण और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरक्षण को ही समाप्त करवा देना चाहते हैं और संविधान तथा देश के कानून ने जो हजारों साल से वंचित रहे लोगों को स्थान दिया था उसको छीन लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा कारखाने बंद किए जा रहे हैं या उनको प्राइवेट कंपनियों को सौंपा जा रहा है। जिनमें निरंतर रोजगार कम हो रहा तथा लाखों वैकेंसी सरकारी विभागों की भरी नहीं जा रही हैं तथा कुछ जगहों में ठेके पर नौकरी दी जा रही है। जिनका वेतन जीने लायक भी नहीं है। बेरोजगार नौजवान घर घर बैठे हैं। मोदी ने प्रतिवर्ष दो करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था किंतु यह वादा वायदा ही रह गया।

भाजपा सरकार दलितों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही है जिसे कम्युनिस्ट पार्टी पूरा नहीं होने देगी तथा पार्टी सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने हेतु कमर कस चुकी है। कमलेश प्रसाद ने कहा कि देश में किसान, मजदूर, व्यापारी और गरीब दो वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लगातार आंदोलन व चेतावनी देने के बाद भी सरकार के कानों में महंगाई कम करने के लिए जूं तक नहीं रेंग रही है और लगातार डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर भारतीय जनता पार्टी व तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। रवि करण ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान व कानून को ताक में रखकर, गरीबों की झुग्गी झोपड़ी और मकान गैर कानूनी रूप से ध्वस्त कर बुलडोजरगिरी का राज चलाकर प्रदेश में भय व दहशत का माहौल पैदा कर रही है जिस पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।

सभा को संदीप पांडेय, विनोद पाल, राजेंद्र कुमार, दादूराम आदि ने संबोधित किया। सभा के बाद महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित आरक्षण, बेरोजगारी, महंगाई और बुलडोजरगिरी पर लिखा ज्ञापन तहसीलदार कर्वी को सौंपा गया। प्रदर्शन व सभा में कमलेश कुमार, हनुमान, संजय प्रधान, राम सारण, प्रदुमन कुमार, रेवती रमण, गोपी, शिव पुराण, रामसागर, राजधर दरबारी, शिव नरेश गुलाब, राजधर, राजकरण यादव सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

सरकार अपनी नीतियों को बदले, अन्यथा सत्ता छोड़े

पेज 16 से जारी...

गुजारा करना मुश्किल हो रहा है परंतु यह संवेदनहीन सरकार इन समस्याओं का कोई समाधान की दिशा में कुछ करने के बजाय विकास के फर्जी दावे करती रहती है। मजदूरों में फूट डालने के लिए सांप्रदायिकता को औजार बना लिया गया है। देश में असमानता में भारी वृद्धि हो रही है; ऑक्सफैम की हाल में आई रिपोर्ट ने इस बढ़ती हुई असमानता को रेखांकित करते हुए कहा है कि देश के चंद कारपोरेटों के हाथ में अधिकाधिक धन–दौलत का संकेन्द्रण हो रहा है। वक्ताओं ने कहा कि देश में जी–हजूरिया पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज्म) को बढ़ावा दिया जा रहा है; हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में अदानी घराने की जिन कारगुजारियों का जिक्र है वह जी–हजूरिया पूंजीवाद को मिल रहे सरकारी प्रोत्साहन एवं संरक्षण का उदाहरण है।

सम्मेलन ने एक घोषणापत्र पारित किया और भारत के करोड़ों मजदूरों का आह्वान किया कि एक दृढ़ संकल्प के साथ आगामी कार्यक्रमों में हिस्सा लें।

घोषणापत्र में कहा गया है:–

एकजुट संघर्षों के हमारे पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मजदूरों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन, हमारे देश के मेहनतकश लोगों से एकजुट संघर्षों को उच्च स्तर तक ले जाने का आह्वान करता है। हमें इस सरकार की विनाशकारी नीतियों के खिलाफ क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपनी लड़ाई तेज करनी होगी। 2023 का पूरा वर्ष सभी स्तरों पर संघर्ष के उच्च रूपों में परिणत होने के लिए एकजुट अभियानों और आंदोलनों का वर्ष होना चाहिए।

मजदूरों का यह राष्ट्रीय सम्मेलन, अपनी 14 सूत्री मांगों के चार्टर को दोहराते हुए, जो नवउदारवादी नीति व्यवस्था के संपूर्ण सरगम के विकल्प को प्रोजेक्ट करता है, इस दिशा में काम करने का संकल्प लेता है और निम्नलिखित कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रस्ताव करता है:

– मार्च 2023 से मई 2023 तक का महीना राज्य/जिला/ और क्षेत्रीय सम्मेलनों के आयोजन के लिए समर्पित होना चाहिए।

– जत्था कार्यक्रमः जून महीने से पदयात्रा/जीप जत्थे/साइकिल जत्थे/मोटरबाइक जत्थे आदि को किया जाना चाहिए। ऐसा कार्यक्रम राज्य सम्मेलनों में तय किया जाना चाहिए।

– जत्था कार्यक्रमों के माध्यम से ये जन अभियान 9 अगस्त को 'भारत छोड़ो दिवस' से राज्य–स्तरीय महापड़ाव में परिणाम होंगे। संयुक्त राजय सम्मेलनों के निर्णय के अनुसार यह कई दिनों का कार्यक्रम भी हो सकता है।

– हड़ताल की कार्रवाईयों सहित क्षेत्रीय संघर्षों का समर्थन और सहयोग किया जाना है।

– दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन के दौरान मजबूत हुई मजदूर–किसान एकता को और आगे ले जाने की जरूरत है। इस वर्ष कुछ संयुक्त कार्यक्रम किए जाएंगे।

वर्ष के अंत में देशव्यापी हड़ताल की कार्रवाई की ओर बढ़ने के लिए आंदोलन कार्यक्रमों को और तेज करने के लिए महापड़ाव कार्यक्रम के बाद की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 5 – 11 फरवरी, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 3.2.2023

सरकार अपनी नीतियों को बदले, अन्यथा सत्ता छोड़े

वाहिदा निजाम

30 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में आयोजित मजदूरों के राष्ट्रीय सम्मेलन ने केन्द्र सरकार को सख्त संदेश दिया है कि भारत का मेहनतकश तबका केंद्र की भाजपा सरकार की घनघोर जन–विरोधी, मजदूर–विरोधी नीतियों से तंग आ चुका है और अब इन नीतियों के विरूद्ध संघर्ष तेज करने का संकल्प लेता है। राष्ट्रीय सम्मेलन ने मजदूरों और आम लोगों के सभी वर्गों के सामने उत्पन्न चिंताजनक स्थिति का संज्ञान लिया। सरकार की नीतियां न केवल मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और जन विरोधी हैं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। ये नीतियां हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए विनाशकारी साबित हुई हैं। इन विनाशकारी नीतियों से देश को बचाने और लोगों को बचाने के लिए मजदूर वर्ग संघर्ष करेगा।

सम्मेलन ने एक निर्विरोध घोषणापत्र पारित किया जिसमें सरकार की विनाशकारी नीतियों का पर्दाफाश करने के लिए एक वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। यह सम्मेलन देश की दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर की यूनियनों एवं ऐसोसिएशन ने आयोजित किया था। सम्मेलन की अध्यक्षता एक दस सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने की। इसमें शामिल थे: अमित यादव (इंटक), बिनोय विश्वम, संसद सदस्य (एटक), राजाश्रीधर (हिन्द मजदूर सभा), डॉ. के. हेमलता (सीटू), आर. पाराशर (एआईयूटीयू), जी.आर. शिवशंकर (टीयूसीसी), लता बेन (सेवा), के.के. बोरा (एआईसीसीटीयू), रशीद खान (एलपीएफ) और शत्रुजीत सिंह (यूटीयूसी)।

सम्मेलन को इंटक उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, एटक महासचिव अमरजीत कौर, हिन्द मजदूर सभा के महासचिव हरभजन सिंह, सीटू महासचिव तपन सेन, एआईयूटीयू कार्यकारिणी सदस्य राजिन्द्र सिंह, टीयूसीसी के अध्यक्ष के. इन्दूप्रकाश मेनन, सेवा की राष्ट्रीय परिषद सदस्य सोनिया जॉर्ज, एआईसीसीटीयू अध्यक्ष राजीव डिमरी, एलपीएफ महासचिव शन्मुगम और यूटीयूसी महासचिव अशोक घोष ने संबोधित किया।

30 जनवरी महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर आयोजित मजदूरों के इस सम्मेलन ने संकल्प किया कि भारत को और भारत के संविधान को सांप्रदायिक एवं कारपोरेट परस्त आरएसएस–भाजपा सरकार से बचाने के लिए भारत का मजदूर वर्ग संघर्ष करेगा। सम्मेलन को संबोधित करते हुए एटक महासचिव अमरजीत कौर ने कठोर वास्तविकता के इस दुखद विरोधाभास की तरफ ध्यान आकर्षित कराया कि आज सत्ता में वह सांप्रदायिक ताकतें बैठी हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की प्रशंसक हैं। उन्होंने कहा कि भारत के मजदूरों का यह अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह उस धर्मनिरपेक्ष एवं बहुलवादी भारत को बचाएं जिसकी महात्मा गांधी ने न केवल परिकल्पना की थी बल्कि उसका निर्माण भी किया। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। सदन ने श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट का मौन रखा। उसके बाद सम्मेलन की कार्यवाही शुरू हुई।

सम्मेलन स्थल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एनेक्सी देशभर से आए ट्रेड यूनियन नेताओं/कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा था। 1500 से अधिक ट्रेड यूनियन नेताओं/कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के अलावा सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि बैंकों, बीमा कंपनियों की यूनियनों, राज्य एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की यूनियनों, पोस्टल, टेलीकॉम, डिफेंस, टीचर्स ऐसोसिएशनों आदि के प्रतिनिधि शामिल थे। इनमें संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों की यूनियनों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में शामिल सभी प्रतिनिधियों में मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई मजदूर विरोधी नीतियों, खासतौर पर श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर 29 श्रम कानूनों के स्थान पर चार श्रम संहिताओं को लाए जाने, जिनके प्रावधान कारपोरेट परस्त और मजदूर विरोधी हैं, के विरूद्ध जबरदस्त आक्रोश था। जब भी मंच से मजदूर नेताओं ने अपने संबोधन में सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की भर्त्सना की तो सम्मेलन में शामिल सभी प्रतिनिधियों ने सरकार विरोधी जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की। सम्मेलन में जबरदस्त आशा और आत्मविश्वास झलक रहा था कि भारत का मजदूर वर्ग भारत और संविधान को बचाने के लिए दृढ़ संकल्प रखता है और इसके लिए डटकर संघर्ष करेगा।

''अपनी विनाशकारी नीतियों को बदलो, वरना सत्ता छोड़ो''–सम्मेलन में पारित घोषणापत्र का यह स्पष्ट संदेश था। सभी ट्रेड यूनियन नेताओं ने अपने भाषणों में यह स्पष्ट किया और दोहराया कि देश के मजदूर वर्ग पर यह सरकार जिस नृशंसता और निर्ममता के साथ हमला कर रही है उसके खिलाफ उठ खड़ा होना आवश्यक हो गया है।

सम्मेलन में पारित घोषणापत्र में कहा गया है कि जरूरत इस बात की है कि मजदूरों और लोगों को जागरूक किया जाए कि उनका असली दुश्मन, उनके दुखों और राष्ट्र के दुखों का कारण केंद्र में कारपोरेटों द्वारा संचालित राष्ट्र विरोधी विनाशकारी मोदी सरकार है। उन्हें इन विनाशकारी नीतियों को बदलना होगा अन्यथा सत्ता से हटना होगा। बड़े पैमाने पर लोगों के साथ फ्रंटलाईन से नेतृत्व करते हुए इस कार्य का निर्वहन करना मजदूर वर्ग के आंदोलन की नियति है।

सम्मेलन ने घोषणा की कि इस दिशा में काम करने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिनमें जत्था कार्यक्रम और जन अभियान जैसे कार्यक्रम शामिल हैं और इन कार्यक्रमों का आयोजन 9 अगस्त को किया जाएगा जब 'भारत छोड़ो'' आंदोलन की तर्ज पर आगामी कार्यक्रमों की शुरूआत की जाएगी।

वक्ताओं ने अपने भाषणों में गहराई से उन सभी समस्याओं जिससे आज सारा देश त्रस्त है–जैसे कि मंदी के स्तर तक गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, भूख और गरीबी में वृद्धि और रोजगार खत्म होने का सिलसिला–पर गहराई से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश के लोग इन गंभीर समस्याओं से त्रस्त हैं और उनके लिए

शेष पेज 15 पर...

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.